04 - सूचना क्रांति के दौर में गांधी की धीमी पत्रकारिता की प्रासंगिकता

05 - संकट में जीवन की विविधता: जैव विविधता संरक्षण की पुकार

A Daily News Magazine

भोपाल

गुरुवार, 22 मई, 2025

06 - नालों की सफाई में बाधा बन रहा अतिक्रमण, बारिश...

07 - देवी अहिल्याबाई होल्कर की तरह महिलाओं को...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 252, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

ट्रंप ने दिया 'तलाक' तो यूरोप को आई इंडिया की याद!

ओंकारेश्वर पांडेय

जब भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद अपनी अपनी जीत हार के दावे और नुकसान के आकलन कर रहे थे और वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप बार बार इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी समय ब्रूसेल्स में यूरोप और ब्रिटेन इतिहास के एक नये अध्याय पर हस्ताक्षर कर रहे थे। एक ऐसा इतिहास जो खामोशी से एक ध्रुवीय विश्व को बहुध्रुवीय दुनिया की तरफ ले जा रहा था। 19 मई 2025 को ब्रूसेल्स की सर्द हवाओं में यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने जो रणनीतिक समझौता किया, उसमें सुरक्षा, रक्षा, यूक्रेन समर्थन, प्रवास, जलवायु, शिक्षा और व्यापार तो शामिल था ही, इसमें अमेरिकी छत्रछाया से इतर एक नया यूरोप बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति की झलक भी थी।

यह समझौता महीनों की उस गोपनीय बातचीत का नतीजा था, जो जनवरी 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप की दी हुई अपमानजनक उपेक्षा और अवहेलना से शुरू हुई थी। यह समझौता ब्रेक्सिट के पुराने जख्मों पर मरहम नहीं, बल्कि यूरोप की उस जिद का प्रतीक है जो अब अमेरिका के तलाकनामे के बाद अपनी नई राह तलाश रही है।

इस साल की शुरुआत में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रेडमार्क सुनहरे बालों को हिलाते हुए व्हाइट हाउस में दोबारा क़दम रखा, तो शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका तमाशा विश्व मंच पर एक नयी पटकथा लिख देगा। एक ऐसी पटकथा, जिसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होकर भी अमेरिका खुद जहां अकेला पड़ता जायेगा, वहीं इस इस राह पर नये कदमों से चलते यूरोप को रूस और चीन से अलग भारत की याद आएगी। उस भारत की जिसने नेहरु के जमाने से ही गुट निरपेक्षता की राह पकड़ी थी। आज यूरोप को लग रहा है कि नेहरु के रास्ते ठीक थे, उसने अमेरिका पर निर्भर रहकर कई दशक गंवा दिये।

20 जनवरी 2025 को, वाशिंगटन डीसी में ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। इसके बाद, 15 मार्च को पेन्सिलवेनिया की एक रैली में उन्होंने नाटो को 'बेकार का बोझ' ठहराया और यूरोप को 'अमेरिकी खजाने पर पलने वाला मेहमान' बताया। 10 अप्रैल को टेक्सास में रूढ़िवादी दानदाताओं के सामने ट्रंप ने ईयू के ग्रीन डील को 'आर्थिक हत्या' करार दिया, यह कहते हुए कि 'अमेरिकी मज़दूर यूरोप के जलवायु सपनों का बोझ क्यों उठाए?'

ट्रंप के ये बयान कोई तात्कालिक तुनकमिजाजी नहीं थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका पहला कार्यकाल (2017-2021) भी इसी तरह के तानों से भरा था, जब उन्होंने नाटो को 'पुराना ढाँचा' कहा, जर्मनी को 'रूस का गुलाम' बताया, और ईयू को अमेरिका का 'लाभ उठाने वाला' करार दिया। उस वक्त तो यूरोप ने सदमे में खामोशी से आहें भरीं, जैसे कोई पुराना मित्र नाराज़ दोस्त की बातें झेल लेता है। मगर अब, 2025 में, इससे मर्माहत और तिलमिलाये यूरोप की आँखों में रोष है, मुट्ठियाँ बँधी हैं, और इरादे पक्के। ट्रम्प का तलाकनामा यूरोप के लिए अपमान नहीं, बल्कि एक नई सुबह का न्योता बन गया है।

जब ट्रम्प के तानों ने यूरोप के गौरव को ललकारा, तो यूरोप की कलम ने विद्रोह की स्याही से जवाब लिखा। 5 मई 2025 को, फ्रांस के अखबार 'ले मॉन्ड' ने अपने संपादकीय में लिखा, 'ट्रम्प ने साफ कर दिया कि यूरोप उनके लिए एक पुराना कोट है, जिसे वे कबाड़खाने में फेंकने को तैयार हैं।' 20 अप्रैल को जर्मनी के डेर स्पीगल ने तंज कसा, 'ट्रम्प हमें इसलिए नीचा दिखाते हैं, क्योंकि वे शक्ति को केवल बम-बारूद में देखते हैं। मगर यूरोप की ताकत उसकी कूटनीति, उसकी स्थिरता, उसका धैर्य है।'

15 अप्रैल को ब्रूसेल्स में यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स (ईसीएफआर) ने अपने पेपर नो लॉन्गर पार्टनर्सः ए पोस्ट-अटलांटिक यूरोप में ऐलान किया कि 'ट्रान्सअटलांटिक गठबंधन अब इतिहास की बात है। स्वायत्तता अब सपना नहीं, बल्कि ज़रूरत है।' तथ्य यह है कि यूरोप और अमेरिका कभी विश्व मंच के दो जिगरी दोस्त थे। 2008 के आर्थिक संकट में, यूरोपीय बैंकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के साथ मिलकर वैश्विक बाजारों को संभाला। मगर ट्रम्प के लिए ये सब पुरानी कहानियाँ हैं, जिन्हें वे लेन-देन के बहीखाते में बदलना चाहते हैं। ट्रम्प माने डील।

जब ट्रम्प के तलाकनामे ने यूरोप को झकझोरा, तो ब्रुसेल्स और लंदन ने एक नया गीत गाया। 19 मई 2025 को, ब्रूसेल्स में यूरोपीय आयोग ने जिस ईयू-यूके रणनीतिक समझौते की जो घोषणा की, वो जनवरी 2025 से शुरू हुई उस गोपनीय बातचीत का नतीजा था, जो ट्रम्प के अपमानजनक बयानों से प्रेरित थी। ट्रम्प के तानों ने नाटो को हिलाकर रख दिया, जैसे कोई पुराना मकान हवा के झोंके से काँप उठे। 15 मार्च 2025 को पेन्सिलवेनिया में ट्रम्प ने नाटो से निकलने की धमकी दी और 5 प्रतिशत जीडीपी रक्षा खर्च की माँग की। नाटो के 32 सदस्यों में से 23 अब 2 प्रतिशत जीडीपी लक्ष्य को पूरा करते हैं, लेकिन 5 प्रतिशत का लक्ष्य दूर की कौड़ी है। 10 जून 2025 को 'द हेग' में होने वाला नाटो शिखर सम्मेलन इस गठबंधन की एकजुटता की कसौटी होगा।

यूरोप अब किसी के भरोसे नहीं बैठा। 15 जनवरी 2024 को, ब्रुसेल्स में ईयू ने यूरोपीय रक्षा संघ की योजना को गति दी, जिसमें ˜ 7.5 बिलियन का रक्षा कोष और संयुक्त कमांड सेंटर शामिल हैं। 15 मार्च 2025 को, यूरोपीय रक्षा औद्योगिक रणनीति की घोषणा हुई, और एक रक्षा आयुक्त नियुक्त किया गया। इन क़दमों ने ईयू को एक स्वतंत्र खिलाड़ी बनाया है। यूरोप का रक्षा उद्योग अभी बिखरा हुआ है, और अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता एक चुनौती है। ट्रम्प के तलाक ने यूरोप को न केवल जगा दिया, बल्कि उसे अपने पंखों पर उड़ने की हिम्मत भी दे दी है।

जब ट्रम्प ने तलाक का नोटिस थमाया, तो यूरोप ने नए दोस्त की तलाश में भारत की ओर देखा। 10 फरवरी 2025 को, नई दिल्ली में ईयू-भारत शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन शामिल हुईं। इस सम्मेलन ने 2021 के भारत-ईयू रणनीतिक रोडमैप को विस्तार देने का फैसला किया। व्यापार वार्ताएँ दिसंबर 2025 तक मुक्त व्यापार समझौते की ओर बढ़ रही हैं। ईयू के साथ भारत की दोस्ती वैश्विक शक्ति संतुलन को नया आकार दे सकती है। रूस, पश्चिम से अलग-थलग, नाटो की दरारों और वाशिंगटन-ब्रूसेल्स के अविश्वास से मजे ले रहा है। मगर सवाल यह हः क्या भारत इस नए विश्व व्यवस्था का नायक बनने को तैयार है? इसके लिए भारत को एक गंभीर, एकजुट, मजबूत और दूरदर्शी राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। लेकिन इससे भी जरूरी है कि हम किसी देश के पिछलग्गू ना बनें।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

तब सुबह की कोमल धूप
छांव की याद लिए
दोपहर के जलते घाम में
हम नमक की तीव्रतम वेगवान नदी को
सहजता से संग-साथ पार कर लेते थे
शाम गये इंतज़ार में होती थी
वही सुबह की धूप
और हम संगीत,हंसी और ठहाकों में
एक साथ सुंदर ख्वाबों के नम आंचल में
भूल जाते थे उस घाम की बरसती आग
यह क्या हुआ देश को कि
सुबह-शाम की वो मीठी रवायत को छोड़
बेवजह घाम ही घाम उठाये
कुछ लोग नष्ट करने पर आमादा हैं
वह प्रकृत कोमल धूप स्व-भाव
हम जिस दुष्चक्र के शिकार हो रहे हैं ...
आओ जगह-जगह बैठकर
उसके आतंक पर बात करें
उससे भी युद्ध करें।

– लीलाधर मंडलोई

वक्फ का इस्लाम में जिक्र

... लेकिन इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। वक्फ (संशोधन) कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हो रही है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, चाहे वो 'वक्फ बाय यूजर' के आधार पर ही क्यों न हो। एसजी मेहता के मुताबिक अगर कोई जमीन सरकारी है तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वह उसे वापस ले ले, भले ही उसे वक्फ घोषित कर दिया गया हो। किसी भी प्रभावित पक्ष ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि संसद के पास इस कानून को पारित करने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया, वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब तक यह साबित न हो जाए, बाकी तर्क विफल हो जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रखा अपना पक्ष, दूसरे दिन भी सुनवाई

केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ को मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि वक्फ इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा है, तब तक इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। मेहता ने कहा,वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है, इस पर कोई विवाद नहीं है।

- **सॉलिसिटर जनरल की दलील- हमने बिना सोचे-समझे बिल नहीं बनाया-** सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जहां मंत्रालय ने एक बिल बनाया और बिना सोच-विचार के वोटिंग कर दी गई हो। कुछ याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय की ओर से नहीं बोल सकते। आपके पास जो याचिकाएं आई हैं, वे ऐसे लोगों ने दायर की हैं जो सीधे इस कानून से प्रभावित नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी ने यह नहीं कहा कि संसद को यह कानून बनाने का अधिकार नहीं था। संयुक्त संसदीय समिति की 96 बैठकें हुईं और हमें 97 लाख लोगों से सुझाव मिले, जिस पर बहुत सोच-समझकर काम किया गया।

ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत

नई दिल्ली (एजेंसी)। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अग्रिम जमानत दी। जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूजा को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पूजा ने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया। वह कोई ड्रग माफिया या आतंकवादी नहीं है। उन पर हत्या (धारा 302) का आरोप नहीं है। कोर्ट ने आगे

कहा- आपके पास कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिससे इस तरह की जांच समय पर हो। उसने सब कुछ खो दिया है, अब कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा- इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही जमानत देनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने जमानत का विरोध किया। कहा कि पूजा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। पूजा खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगता कोटे से आरक्षण लेने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का 23 दिसंबर 2024 का आदेश पलट दिया था। पूजा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश में कुछ ऐसी टिप्पणी हैं जो पूजा के खिलाफ प्रयोग हो सकती हैं।

अभियान की उपलब्धियां उत्कृष्ट टीम वर्क और प्लानिंग का नतीजा: राज्यपाल

संयमित जीवन शैली का पालन भारतीय संस्कृति की परिपाटी : मुख्यमंत्री यादव

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने सौ दिवसीय निःक्षय शिविर अभियान के संचालन में, टी.बी. उन्मूलन प्रयासों को विस्तारित करने, समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग से फूड बास्केट वितरण करने और 5 हजार से अधिक टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायतों की उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य की उपलब्धियां उत्कृष्ट टीमवर्क और प्लानिंग का नतीजा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है

कि भारतीय संस्कृति में 'उत्तम सुख निरोगी काया' का भाव प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। परिवारों में ऋतु आधारित आहार-विहार और संयमित जीवन शैली के विचार के व्यवहार में पालन की परिपाटी रही है। राज्यपाल श्री पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 100 दिवसीय निःक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह और स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ राजभवन स्थित सांदीपनि सभागार में किया। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि टी.बी. के उन्मूलन के लिए संक्रमण नियंत्रण और सही तरीके से समय पर पूरी मात्रा में दवा लेने के संबंध में भी जन जागृति के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि टी.बी. की दवा को बीच में छोड़ने से रोगी दवाओं के प्रति ड्रग रजिस्टेंट हो जाता है। इससे इलाज कठिन और संक्रमण फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। उन्होंने नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए स्वस्थ यकृत मिशन शुभारंभ के लिये सरकार की सराहना की। राज्यपाल श्री पटेल ने कार्यक्रम में स्वस्थ लिवर की जांच के लिए बताए गए आसान तरीको से जांच करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पतंजलि से लेकर घेरंड संहिता तक से हमें, काया को निरोगी बनाए रखने के सूत्र प्राप्त होते हैं। भारतीय ज्ञान ग्रंथ भी यही विचार देते हैं कि जैसे पका हुआ फल अपना जीवन पूर्ण करता है, वैसे ही व्यक्ति भी अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्यपाल श्री पटेल की प्रदेश वासियों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता सराहनीय है। राज्य सरकार वर्ष 2028 तक प्रदेश को टी.बी. मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्रत्येक स्तर पर सघन प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में सम्मानित टी.बी. चैंपियंस के प्रयासों और टी.बी. को हराने के उनके मन के संकल्प और प्रयासों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 72 वर्षीय पद्म भूषण डॉ. सरीन की नियमित दिनचर्या और प्रतिदिन व्यायाम करने की जानकारी देते हुए सभी को व्यायाम और नियमित दिनचर्या के लिए प्रेरित किया है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सौ दिवसीय निःक्षय शिविर अभियान में केन्द्र सरकार द्वारा केवल मध्य प्रदेश का सम्मान किया गया है।

छत्तीसगढ़ में फिर नक्सलियों की आ गई शामत, 27 हुए ढेर

20 शव और कई हथियार बरामद,1 जवान भी शहीद

जगदलपुर (एजेंसी)। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के जंगल में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी 27 शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। वहीं फायरिंग में डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) का एक जवान शहीद हो गया है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर मुठभेड़ चल रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के बोटेर में नक्सलियों का

पोलित ब्यूरो सदस्य और नक्सल संगठन का महासचिव बसवा राजू मौजूद है। इसी आधार पर फोर्स को रवाना किया गया था। अबूझमाड़ के बोटेर पहुंचते ही जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षाबलों के इस ऑपरेशन को प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बड़ी कामयाबी बताया है। पुलिस ने 7 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेंगुट्टा ऑपरेशन की जानकारी दी थी। छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर स्थित करेंगुट्टा के पहाड़ों पर सुरक्षाबलों ने 24 दिनों तक चले ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया था। इनमें 16 महिला और 15 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इस भीषण गोलीबारी में जवानों ने एक कुख्यात माओवादी को भी मार गिराया है, जिसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपये का ईनाम था।

बिहार तक पहुंची एमपी के मंत्री 'विजय शाह' मामले की आंच

पटना (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह एक विवादित बयान को लेकर गंभीर विवादों में घिर गए हैं। शाह ने एक कथित बयान में भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को 'आतंकियों की बहन' बताया, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। अब एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल भी कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। चिराग पासवान के बाद अब जेडीयू ने विजय शाह का इस्तीफा मांग कर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मंत्री विजय शाह के बयान से नाराज होकर एनडीए में शामिल सहयोगी दलों ने इसे 'असंवेदनशील' और 'अस्वीकार्य' बताया है। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए जेडीयू प्रवक्ता डॉ जितेंद्र कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग

चिराग के बाद जेडीयू ने बढ़ाया सियासी तनाव,उड़ापोह में बीजेपी नेतृत्व

है। हमारे नेता ने कभी भी क्राइम, करप्शन और कम्युनिजम पर कभी कोई समझौता नहीं है। राजनीति में नैतिकता, सदाचार और मर्यादा का इकबाल बुलंद रहे। इसके लिए ऐसे बयानवीर नेताओं का इस्तीफा होना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी विजय शाह के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, अगर शाह मेरी पार्टी में होते, तो मैं उन्हें आजीवन निष्कासित कर देता। चिराग ने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि

शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

शाह के बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को फटकार लगाई और भविष्य में जिम्मेदारी से बयान देने की सख्त हिदायत दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 38 °c | न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 22 मई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

मध्यप्रदेश में 7 शहर स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल

भोपाल। प्रदेश में शहरों के समुचित विकास, आर्थिक सुधार, नागरिक जीवन शैली में सुधार के उद्देश्य से चयनित 7 शहरों (स्मार्ट सिटी) में कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर का चयन प्रथम चरण में स्मार्ट सिटी मिशन में किया गया था। दूसरे चरण में ग्वालियर और उज्जैन का चयन किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन में तीसरे चरण में सतना और सागर चयन किया गया। देश में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरूआत 25 जून 2015 को की गई थी। इसके बाद से 3 चरणों में मध्यप्रदेश के इन 7 शहरों का चयन किया गया। स्मार्ट सिटी योजना का क्रियान्वयन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत किया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक चयनित शहर के लिये एक हजार करोड़ रूपये ग्रांट का प्रावधान किया गया।

अखिलेश को दूर भगाना है, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना है

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर सोशल मीडिया पर हुई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते गर्मा गई है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी (सपा)

से जुड़े एक सोशल मीडिया हैंडल ने ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर यह टिप्पणी सामने आते ही भाजपा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि यह टिप्पणी ब्राह्मण समाज का अपमान है और समाजवादी पार्टी जानबूझकर जातिवाद को बढ़ावा दे रही है।

पाकिस्तान के सिंध में पानी को लेकर भारी हिंसा

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पानी को लेकर जबरदस्त हिंसा की गई है। पानी को लेकर कई हफ्तों से चल रहा ये बवाल अब हिंसक हो चुका है। डॉन के मुताबिक मंगलवार को सिंध प्रांत के गृह मंत्री जिया लंजर के गृह जिले नौशहरो फिरोज के मोरो शहर में

हुई झड़पों के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। इसके अलावा सिंध प्रांत के गृहमंत्री के घर को प्रदर्शनाकियों ने जला दिया है। डॉन के कहा है कि भीषण हिंसा में एक डीएसपी समेत छह अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गये हैं। इसके अलावा दर्जनों अन्य लोगों के भी घायल होने की रिपोर्ट डॉन ने दी अपनी रिपोर्ट में दी है। डॉन ने कहा है कि रास्तों पर कई गाड़ियों को जला दिया गया है और अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को हिंसा तब भड़की जब पुलिस ने सिंधु नदी पर निर्माण के खिलाफ लाठी भांजनी शुरू कर दी।

प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में होगा सबसे बड़ा स्वागत

अहमदाबाद (एजेंसी)। भारतीय सेना के सटीक और सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां देश के सांसद विदेश में पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलेंगे तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे में अभूतपूर्व स्वागत होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26 मई को वडोदरा पहुंचने पर 25 हजार महिलाएं सिंदूर की सलामती के लिए अभिनंदन करेंगे। पीएम मोदी वडोदरा एयरपोर्ट पास ही एक रोड शो में महिलाओं के अभिनंदन को स्वीकार करेंगे। पीएम का यह रोड शो वडोदरा एयरपोर्ट पास होगा। इसके बाद वह दाहोद के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दो बार ही बोले हैं। उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा पर राष्ट्र को संबोधित किया था।

गंगा नदी को इंटरनेशनल मार्गों से जोड़ेगा मोदी का है यह प्रोजेक्ट

● बिहार में जल्द शुरू होगी वॉटर मेट्रो, राजधानी पटना से शुरुआत ● किराया भी होगा कम, गंगा के साथ अन्य जलमार्गों को भी जोड़ेगा

पटना (एजेंसी)। बिहार में जल्द ही वॉटर मेट्रो शुरू होने वाली है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो बिहार में गंगा नदी को नेशनल और इंटरनेशनल जलमार्गों से जोड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट से बिहार के लोगों को सड़क पर ट्रैफिक की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। इस साल अगस्त में पटना मेट्रो के पहले चरण का संचालन शुरू होगा। उसके बाद वॉटर मेट्रो चलाने की तैयारी होगी। ये वॉटर मेट्रो उत्तर बिहार को पटना मेट्रो के स्टेशन से जोड़ने वाली है। इससे न केवल रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए आसान होगी, बल्कि पर्यटकों को भी काफी फायदा होगा। इसके लिए केरल की कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की तीन अधिकारी पटना आए थे। उन्होंने चार दिन तक इस योजना पर काम किया और गंगा नदी के कई हिस्सों का सर्वे किया। चलिए आपको बताते हैं

आखिर क्या रहेगा वॉटर मेट्रो का किराया।

सरकारी टीम ने कई जगहों का अध्ययन किया है, जिनमें उत्तर भारत के गंडक, सोनपुर, हाजीपुर, कोनहरा, दानापुर, दीघा, बिदुपुर, गायघाट और पहलेजा घाट जैसे जल क्षेत्र शामिल हैं। ये जानकारी इंडियन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के डायरेक्टर अरविंद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि केरल सरकार की मदद से केरल के कोच्चि शहर में लोगों के लिए सस्ती कीमत पर पानी से यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। वॉटर मेट्रो की योजना की शुरुआत गंडक से चलाकर होगी, यही नहीं बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी वॉटर मेट्रो की शुरुआत होगी। इन राज्यों के कुछ शहर प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, गांधी नगर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, बंगाल, गोवा, असम के दुबरी व गुवाहाटी, मंगलुरु, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मुंबई व वसई, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप भी शामिल हैं। गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र नदी, डल झील, अंडमान और लक्षद्वीप में द्वीपों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वॉटर मेट्रो के किराए को लेकर बताया गया है कि मेट्रो का किराया 20 से 40 रुपए रहेगा। ऐसे में वॉटर मेट्रो का किराया दिल्ली मेट्रो से कम रहेगा। दिल्ली मेट्रो का अधिकतम किराया 60 रुपए है, लेकिन वॉटर मेट्रो का अधिकतम किराया ही 40 रुपए होगा। इस वॉटर मेट्रो में 50 यात्री के बैठने की क्षमता होगा और उनके साथ 50 यात्री खड़े होकर सफर कर पाएंगे। यानी 100 यात्रियों के सफर करने की व्यवस्था यहां है।

सीएम ने देखी पीएम के महिला सम्मेलन की तैयारियां

भोपाल के जंबूरी मैदान पर अफसरों से की चर्चा, कहा-रिकॉर्ड बनेगा

भोपाल। 31 मई को एमपी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं के बड़े कार्यक्रम होंगे। भोपाल के जंबूरी मैदान पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम डॉ मोहन यादव ने 31 मई को भोपाल के जंबूरी मैदान पर देवी अहिल्याबाई की 300वीं

जन्म जयंती के मौके पर होने वाले महिला सम्मेलन की तैयारियों को देखा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी कैलाश मकवाना, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह और तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जंबूरी मैदान पर निरीक्षण के दौरान सीएम ने कहा- गोविंदपुरा विधानसभा का ये ऐतिहासिक स्थल एक बार फिर रिकॉर्ड बनाएगा। महारानी अहिल्याबाई का अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 31 मई को जन्म जयंती वर्ष है। इस मौके पर भारत सरकार और मप्र सरकार ने मिलकर अहिल्या उत्सव के पूरे वर्ष के कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में महिला सम्मेलन का आयोजन होगा। सीएम ने कहा- हमने निर्णय किया है कि नारियों को स्वरोजगार मिले। उनकी आमदनी बढ़े। घर में उनका सम्मान बढ़े। इसके लिए प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूह, जिनमें लखपति दीदियों शामिल हैं, उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। पीएम मोदी का सपना है कि हमारी बहनें लखपति बनें। इसी प्रकार से उद्यमशीलता में हमारी बहन बेटियां जो काम कर रहीं हैं। उनके कामों का प्रदर्शन करते हुए लगभग दो लाख बहनों का बड़ा आयोजन भोपाल में 31 तारीख को करने वाले हैं। सीएम ने कहा- जैसा हमारा भोपाल हर बार एक रिकॉर्ड बना रहा है। बीते फरवरी में पीएम की मौजूदगी में जीआईएस का आयोजन करके बीते एक वर्ष तक औद्योगिकीकरण का एक बड़ा अभियान चलाया था। उसके एक वर्ष पूरे होने पर विश्व स्तर का कार्यक्रम किया था। बहनों को जोड़कर उसी तरह का कार्यक्रम अहिल्या माता की जयंती पर कर रहे हैं। कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अलग-अलग विभागों में बहनों के कल्याण के जो काम चल रहे हैं। रेहडी पटरी से लेकर लघु कुटीर उद्योग , एमएसएमई और बड़े उद्योगों के साथ स्वयं सहायता समूहों के बड़े ग्रुप को उद्योगों में परिवर्तित कराएं। किसानों के लिए कृषि आधारित नए उद्योगों में बहनों की भागीदारी हो। दुध उत्पादन में स्वयं सहायता समूह भागीदारी निभाकर गोशालाएं चलाए और दूध उत्पादन बढ़ाए। मछली पालन से लेकर हर क्षेत्र में बहनों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों। इस दिशा से यह आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें तो हमारे भारत की प्रगति बगैर बहनों के अधूरी है। वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भोपाल आगमन को लेकर मप्र भाजपा इस काम में आज से ही जुट गई है। मुख्यमंत्री जी ने जैसी परिकल्पना दी है। हमारी सरकार के इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका होगी। नीचे स्तर से कार्यकर्ता जुटेंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने सीजेआई गवई को परमानेंट स्टेट गेस्ट बनाया

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के चीफ जस्टिस की यात्रा के दौरान राज्य में आधिकारिक शिष्टाचार का पालन तय करने के लिए प्रोटोकॉल गाइडलाइन्स जारी की हैं। मंगलवार देर शाम जारी गाइडलाइन्स के तहत, सीजेआई बीआर गवई को आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र में परमानेंट स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है। जस्टिस बीआर गवई 14 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद 18 मई को पहली बार महाराष्ट्र गए थे। हालांकि, मुंबई में उन्हें स्टेट चीफ सेक्रेटरी,डीजीपी या मुंबई पुलिस कमिश्नर में से कोई भी रिसीव करने नहीं आए थे, जिसपर सीजेआई गवई ने नाराजगी जाहिर की थी। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। सोमवार को राज्य के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उन्होंने प्रोटोकॉल में चूक के लिए राज्य सरकार की ओर से सीजेआई गवई से फोन पर माफी मांगी है। स्टेट गेस्ट को एयरपोर्ट पर स्वागत-विदाई देने

का नियम महाराष्ट्र स्टेट गेस्ट रूल्स, 2004 के अनुसार, स्टेट गेस्ट के तौर पर नामित या माने जाने वाले किसी पदाधिकारी को राज्य प्रोटोकॉल सब-डिवीजन की तरफ से एयरपोर्ट पर स्वागत और विदाई की व्यवस्था की जाती है। जिलों में कलेक्टर ऑफिस नामित प्रोटोकॉल अधिकारियों को रिसीव करने या छोड़ने की व्यवस्था करता है। अब महाराष्ट्र में परमानेंट स्टेट गेस्ट के तौर पर नामित किए जाने के बाद सीजेआई सभी प्रोटोकॉल-संबंधी सुविधाओं के हकदार होंगे। उन्हें राज्य के किसी भी हिस्से में अपनी यात्रा के दौरान आवास, गाड़ी की व्यवस्था और सुरक्षा दी जाएगी। चीफ जस्टिस के मुंबई दौरे के दौरान चीफ सेक्रेटरी या उनके सीनियर प्रतिनिधि, डीजीपी या सीनियर प्रतिनिधि उनका स्वागत करेंगे। किसी जिले के दौरे पर वहां के जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर या एसपी या उनके सीनियर अफसरों को सीजेआई का स्वागत करने का निर्देश दिया गया है। सीजेआई ने कहा था- महाराष्ट्र के अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते मुंबई में 18 मई को महाराष्ट्र-गोवा बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस बीआर गवई का सम्मान समारोह रखा था।

ईडी बोली-सोनिया-राहुल के खिलाफ केस बनता है

● कोर्ट में कहा-अपराध की आय से 142 करोड़ कमाए ● नेशनल हेराल्ड केस की अगली सुनवाई अब जुलाई में

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में चौथी सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट को बताया कि, पहली नजर में सोनिया और राहुल के खिलाफ केस बनता है। दोनों ने अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए हैं। ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपी तब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे जब तक कि प्रवर्तन निदेशालय ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति

जब्त नहीं कर ली। ईडी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि, इस मामले में 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई होगी। नेशनल हेराल्ड केस 2012 से चल रहा है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। यह भी कहा गया कि अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए आपराधिक गतिविधियां की गईं, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है। एसवी राजू और ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन द्वारा प्रस्तुत शुरुआती दलीलों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश ने मामले को 2 जुलाई से 8 जुलाई तक शेष दलीलों के लिए सूचीबद्ध कर दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अब इस मामले को दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

बचाव पक्ष के वकील ने ईडी द्वारा सौंपे गए 5000 पन्नों के भारी भरकम दस्तावेजों के मद्देनजर जुलाई में सुनवाई का आग्रह किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के शेयरों से संबंधित कुछ सवाल उठाए और पूछा कि क्या कंपनी के शेयरधारक इसकी संपत्तियों के मालिक हैं। ईडी के विशेष वकील ने इस आधार पर दलील दी कि कांग्रेस पार्टी के दानदाताओं के साथ धोखाधड़ी की गई।

अब यूपी बनेगा दिव्यांग शिक्षा का राष्ट्रीय हब

● योगी बोले-सभी 18 मंडलों में खुलेगा पुनर्वास केंद्र ● विशेष विश्वविद्यालयों में कौशल पाठ्यक्रमों पर जोर

लखनऊ (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 'दिव्यांग पुनर्वास केंद्र' बनाए जाएं, जहां शिक्षा, पुनर्वास और कौशल विकास से जुड़ी सेवाएं मिल सके। सीएम ने लखनऊ स्थित डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय और चित्रकूट स्थित जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने इन संस्थानों के राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, दिव्यांगजनों की शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र बन सकता है। कॉकलियर इंप्लांट योजना की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा, अगर इस योजना का असली लाभ देना है, तो इसका उपचार बाल्यावस्था में ही शुरू हो। उन्होंने निर्देश दिए कि 214 लाभान्वित बच्चों की हेल्थ रिपोर्ट तैयार की जाए और परिवारों से संवाद सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि 15 लाख दिव्यांगजनों ने यू डीआईडी पोर्टल पर पंजीकरण करवा लिया है।

ऑपरेशन सिंदूर के सहारे शुरू हुई बंगाल चुनाव की तैयारी !

● सीएम ममता बनर्जी के दो बड़े फैसले कर रहे हैं इसी ओर इशारा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े दो बड़े फैसले लिए हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने विदेश दौरे पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में पार्टी सांसद यूसुफ पठान की जगह अभिषेक बनर्जी का नाम आगे किया और दूसरा पांच सदस्यीय एक टीएमसी प्रतिनिधिमंडल पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू और कश्मीर की जमीनी हालात को समझने के लिए भेजना तय किया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए प्रदेश की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के इन दोनों फैसलों को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर इस वजह से, क्योंकि विपक्षी बीजेपी उन पर हिंदू-विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर से टीएमसी सांसद बने यूसुफ पठान के

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में जाने से पीछे हटने के बाद पार्टी की ओर से एक्स पर जानकारी दी गई कि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को आतंकवाद के खिलाफ भारत के वैश्विक रुख के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है। उनकी आवाज शांति, न्याय और वैश्विक सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाएगी। इससे पहले ममता ने कहा था कि उनकी पार्टी से कोई भी विदेश नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मूल पार्टी को प्रतिनिधिमंडल के लिए कोई अनुरोध नहीं आया।

कश्मीर जा रहे हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का क्या

बीजेपी ने बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल के सदस्यों को जम्मू कश्मीर भेजने के ममता के फैसले पर कहा कि यह सब वोट बैंक की राजनीति के तहत हो रहा है। बंगाल क उत्तर 24 परगना में पार्टी नेता दिलीप घोष बोले,पाकिस्तान के खिलाफ जैसा जनमत बना है देशभर में, टीएमसी ने देखा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो राजनीति करना मुश्किल है...केवल मुस्लिम वोट की तरफ देखते हुए इस तरह का स्टेप लेते हैं वो लोग। उन्होंने ममता की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा,आप कश्मीर में प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं का नुकसान हुआ है, घर तोड़ा गया है, मंदिर तोड़ा गया है, दो-तीन हत्याएं हुई हैं, वहां कोई नहीं जाता है।

● टीएमसी मुसलमानों को मुट्ठी में रखना चाहती है- ममता के इस हृदय परिवर्तन पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल के बाहर कौन जानता है... यूसुफ पठान को लोग बाहर भी जानते हैं, वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं.... आप मुसलमानों को मुट्ठी में रखना चाहते हैं..उनको बुर्के बनाके रखेंगे...उनको मदरसा की शिक्षा देंगे..मॉडर्न शिक्षा नहीं देंगे.... इसलिए अभिषेक बनर्जी का नाम आगे किया गया और यूसुफ पठान का नाम वापस लिया गया... यूसुफ पठान को बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि वे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तो हैं, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी कमजोर है। ममता बनर्जी के जिस दूसरे बड़े फैसले की बात हुई, वह है टीएमसी के पांच सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल को जम्मू और कश्मीर के दौरे पर भेजना। यह दौरा पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर हो रहा है। इस दल में तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, सागरिका घोष, ममता ठाकुर और पश्चिम बंगाल के मंत्री मानस भुनिया शामिल हैं।

उज्जैन सिंहस्थ के लिए 19 इंजीनियरों कर्मचारियों की पदस्थापना

प्रभारी अधीक्षण यंत्री को कार्यपालन यंत्री बनाया, एई, एसई, ड्राफ्ट्समैन की भी पोस्टिंग

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा बुधवार को सिंहस्थ 2028 के कामों में तेजी लाने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक के पूर्व उज्जैन में 19 सहायक यंत्री, उपयंत्री, अनुरेखक और स्टाफ की पोस्टिंग की गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश में सूची में शामिल विभाग के सभी इंजीनियर और कर्मचारियों की पदस्थापना सिंहस्थ संभाग और उपसंभाग उज्जैन में की गई है।

लोक निर्माण विभाग ने तबादलों पर बैन हटने के बाद अब तक तीन तबादला आदेश जारी किए हैं। तीसरे आदेश में जो भी अधिकारी कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं वे सभी उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियों को जल्द पूरा कराने के लिए उज्जैन में ही पदस्थ किए गए हैं। इस आदेश में भोपाल में प्रभारी अधीक्षण यंत्री का काम देख रहे एक सहायक यंत्री को उज्जैन में प्रभारी कार्यपालन यंत्री सिंहस्थ संभाग पदस्थ किया गया है। अवनींद्र सिंह सहायक यंत्री को प्रभारी अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मंडल क्रमांक एक-भोपाल से प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ संभाग उज्जैन पदस्थ किया गया है। कुबेर सिंह यादव उपयंत्री को प्रभारी सहायक यंत्री कार्यालय कार्यपालन यंत्री भवन संभाग क्रमांक दो भोपाल से लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ संभाग उज्जैन पदस्थ किया गया है। शुभम रावत उपयंत्री को लोक निर्माण विभाग उज्जैन संभाग से लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ संभाग उज्जैन पदस्थ किया गया है। पुरुषोत्तम हेड़ाऊ सहायक ग्रेड दो को लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2 भोपाल से लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ संभाग उज्जैन में पदस्थ किया गया है। ईश्वरलाल पोरवाल सहायक ग्रेड 3 को लोक निर्माण विभाग उपसंभाग तराना उज्जैन को लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ संभाग उज्जैन स्थानांतरित किया गया है। अनुरेखक श्रेय शुक्ला को लोक निर्माण विभाग संभाग उज्जैन से लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ संभाग उज्जैन स्थानांतरित किया गया है। रणछोड़ भृत्य को गैंगमैन सिंहस्थ उपसंभाग मुनिनगर उज्जैन से लोक निर्माण सिंहस्थ संभाग उज्जैन पदस्थ किया गया है। समीक्षा शुक्ला सहायक यंत्री लोक निर्माण उपसंभाग मऊगंज को अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ उपसंभाग क्रमांक दो उज्जैन पदस्थ किया गया है। राजेश कुमार यादव उपयंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-2 भोपाल को लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ उपसंभाग क्रमांक 2 के लिए स्थानांतरित किया गया है। मलय श्रीवास्तव उपयंत्री लोक निर्माण उपसंभाग क्रमांक 2 को लोक निर्माण उपसंभाग क्रमांक 2 उज्जैन पदस्थ किया गया है। राजीव श्रीवास्तव उपयंत्री लोक निर्माण विभाग भवन पीआईयू क्रमांक एक भोपाल को लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ उपसंभाग क्रमांक 2 उज्जैन पदस्थ किया गया है।

इनको भी किया सिंहस्थ उज्जैन में पदस्थ

सिंहस्थ उपसंभाग के लिए जिन अन्य कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया है उसमें प्रदीप लहाने सहायक ग्रेड दो को लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी संभाग उज्जैन से लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ उपसंभाग क्रमांक दो उज्जैन पदस्थ किया गया है। मनोज गवई सहायक ग्रेड 3 को मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग उज्जैन संभाग से लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ उपसंभाग क्रमांक दो पदस्थ किया गया है। शिवानी बावनकर सहायक ग्रेड 3 को लोक निर्माण विभाग उज्जैन संभाग से लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ उपसंभाग क्रमांक दो उज्जैन पदस्थापना मिली है। गैंगमैन भैरू को सिंहस्थ उपसंभाग अनुभाग मुनिनगर उज्जैन से सिंहस्थ उपसंभाग क्रमांक दो उज्जैन स्थानांतरित किया गया है। हरिओम पाटिल उपयंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग क्रमांक दो नर्मदापुरम को लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ सेतु निर्माण उपसंभाग उज्जैन पदस्थ किया गया है। अजय हारोड़ उपयंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग नौगांव छतरपुर को लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ सेतु उपसंभाग उज्जैन के लिए स्थानांतरित किया गया है। उपयंत्री रमेश भूरिया को लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सैलाना जिला रतलाम से लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ सेतु निर्माण उपसंभाग उज्जैन पदस्थ किया गया है। अनुरेखक रवि शर्मा को कार्यालय अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु मंडल ग्वालियर से लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ सेतु निर्माण उपसंभाग उज्जैन पदस्थ किया गया है। इसके पहले लोक निर्माण विभाग ने 41 इंजीनियरों का तबादला आदेश मंगलवार शाम को जारी किया था। इसमें दो उपयंत्री और 39 सहायक यंत्री अलग-अलग जिलों में पदस्थ किए गए हैं। इसके पूर्व एक अन्य आदेश में सहायक यंत्रियों को अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री की जिम्मेदारी सौंपे जाने का आदेश जारी किया जा चुका है।

भोपाल रेप-ब्लैकमेलिंग केस में बड़े आपराधिक गिरोह की आशंका

एनसीडब्ल्यू ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट; कहा-छात्राओं को महंगे गिफ्ट-गाड़ियों का लालच देकर फंसाया

भोपाल। भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग केस में नेशनल कमीशन फॉर वूमेन की जांच समिति ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कहना है कि आरोपियों ने छात्राओं को महंगे गिफ्ट और लग्जरी गाड़ियों का लालच देकर फंसाया। इसके बाद नशा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। आरोपियों ने पीड़िताओं को धमकाया भी कि वे अन्य छात्राओं को भी इनके चंगुल में फंसाए, वर्ना ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए जाएंगे। आयोग का कहना है कि इस मामले में सिर्फ यौन अपराध ही नहीं, बल्कि जबरन धर्म परिवर्तन और संगठित आपराधिक नेटवर्क की भी भूमिका सामने आ रही है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम डॉ. मोहन यादव और राज्यपाल मंगुभाई पटेल को सौंपी है। इसमें पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की है। NCW की टीम में पूर्व आईपीएस अधिकारी निर्मल कौर, वकील निर्मला नायक और अंडर सेक्रेटरी आशुतोष पांडे शामिल थे। यह टीम 3 से 5 मई तक भोपाल दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने पीड़ित छात्राओं, उनके परिवारों, पुलिस अधिकारियों और कॉलेज प्रशासन से मुलाकात की। रिपोर्ट में कहा है कि कुछ मामलों में पीड़िताओं पर धर्म बदलवाने का दबाव भी डाला गया। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि आरोपी सामान्य आर्थिक स्थिति से थे, लेकिन उनका भड़कीला जीवन-शैली इस बात की ओर इशारा करता है कि उनके तार ड्रग तस्करी या किसी बड़े आपराधिक नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। महिला आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले की गहराई से जांच कराए, जिसमें बाहरी फंडिंग, वैचारिक प्रभाव और प्राइवेट संस्थानों द्वारा सरकारी योजनाओं, जमीन और शिक्षा निधियों के दुरुपयोग की संभावना को भी शामिल किया जाए।

बुजुर्ग ने सिर झुकाया, पगड़ी पैरों में डाली, मांगा न्याय

तहसीलदार के सामने जमीन पर नाक लगाकर की मिन्नत

भोपाल। मंदसौर में एक बुजुर्ग व्यक्ति का कहना है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने तहसीलदार के सामने सिर झुकाया और पगड़ी पैरों में रख दी। मोहनलाल बलाई नाम के इस बुजुर्ग का कहना है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं लंबे समय से परेशान होने के साथ-साथ उन्हे

राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने अधिकारी द्वारा अनुचित व्यवहार की भी बात कही है। पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले पर जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी का भी बयान सामने आया है। उनके बयान के हिसाब से बुजुर्ग एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की मांग कर रहे हैं। बरखेड़ा देवडूंगरी के रहने वाले मोहनलाल बलाई अन्य आम लोगों की तरह अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए जनसुनवाई में अपनी परेशानी लेकर गए थे। जब वहां भी कोई हल नहीं निकला, तो वे कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर बैठ गए। उन्हे देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। देखते ही देखते मामला अधिकारियों के पास पहुंच गया। मामले की जानकारी लगते ही तहसीलदार सोनिका सिंह को मौके पर पहुंचीं।

बहनों ने पाकिस्तान में घुसकर मारा, भाई गए तो क्या होगा

बागेश्वर बाबा ने चीन और पाकिस्तानी को बुरी तरह लताड़ा

भोपाल। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यूं तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर वह अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। फिलहाल वह बिहार के मुजफ्फरपुर में कथा कह रहे हैं। मंगलवार रात उन्होंने दिव्य दरबार लगाया। उन्होंने कहा कि देश में जातिवाद के नाम पर चर्चा हो रही है, हमें जातिगत जनगणना से दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत की जातियों की गिनती के बजाए ये गिनती की जाए, अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, ताकि गरीबों के लिए कुछ किया जाए। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से जुड़ी जाति नहीं होती। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा होगा तो गरीब का भला होगा, क्षेत्र का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा, तब भारत विश्वगुरु होगा। बाबा ने कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। धर्म विरोधियों के, बिगड़ैल औलाद के रूप में पाकिस्तान ने अपना बुरा चेहरा दिखाया। ये 1965, 1971 का भारत नहीं है। ये 2025 का भारत है, जिसने घर में घुसकर मारा। हमारी माताओं के सुहाग को उजाड़ा। हमें गर्व है, भारत की आर्मी पर, सेना पर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर घर में घुसकर मारा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि एक दिन मैं घर पर टीवी देख रहा था, जब भारत की सेना पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ रही थी, तब मैं हंस रहा था और बोल रहा था कि सिंदूर तो झांकी है, हल्दी, मेहंदी बाकी है।

लुटेरी दुल्हन का एक शादी का चार्ज 50 हजार रुपए

भोपाल में एजेंट से बोली-जल्द शादी करवा रहे हो या दूसरे एजेंट से बात करूं

भोपाल। भोपाल के छोला से पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन अनुराधा को फर्जी शादी करने के लिए 50 हजार रुपए मिलते थे। पुलिस मान रही थी कि अनुराधा गैंग के लिए सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन उसके मोबाइल की जांच के बाद पता चला कि वह सक्रिय सदस्य की तरह काम कर रही थी। उसने एक एजेंट को धमकाते हुए कहा- जल्दी मेरी शादी करवा रहे हो या फिर किसी और एजेंट से बात करूं? ये मैसेज अनुराधा के फोन में मिला है। राजस्थान पुलिस ने मंगलवार को भोपाल में फर्जी शादियों के जरिए लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाली अनुराधा को गिरफ्तार किया था। आरोपी अनुराधा पासवान अब तक करीब 25 लोगों से नकली शादी कर उन्हें ठग चुकी है। वह कई एजेंट्स के संपर्क में थी। अब पुलिस को यकीन हो गया है कि यह मामला ठगी के रैकेट का है, जिसमें दुल्हन, एजेंट और अन्य सदस्य पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे। अब तक की पूछताछ में अनुराधा ने बताया कि वह एक शादी के 50 हजार रुपए लेती थी। बाकी की राशि गैंग के सदस्य बांट लेते थे। पुलिस की जांच में पता चला कि गिरफ्तारी से ठीक सात दिन पहले अनुराधा ने भोपाल के छोला इलाके में रहने वाले गब्बर नाम के युवक से शादी की थी। वह उसी के घर में रह रही थी। इसी दौरान राजस्थान के रहने वाले विष्णु शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई कि उसने अनुराधा से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के तीन दिन बाद ही वह नकदी, जेवर और मोबाइल लेकर फरार हो गई। अनुराधा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कोल्हुई बाजार की रहने वाली है। उसकी 2016 में विशाल पासवान से शादी हुई थी। पति से विवाद के बाद वह भोपाल आई और यहां एक महिला के संपर्क में आकर इस गिरोह का हिस्सा बन गई। अनुराधा ने पुलिस को बताया कि पति की डांट और नाराजगी ने उसने यह रास्ता चुना।

गिरोह के सदस्य भोपाल और आसपास के

पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में रोशनी, सुनीता, रघुवीर, गोलू, मजबूत सिंह यादव और अर्जुन नाम के लोग सक्रिय हैं। पुलिस को शक है कि गिरोह में कई और युवतियां भी शामिल हो सकती हैं। इसमें रोशनी छोला मंदिर इलाके की है, सुनीता मंडीदीप की, अर्जुन निवासी गांधी नगर और मजबूत सिंह यादव, रघुवीर, गोलू भोपाल के अन्य इलाकों से हैं। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने भोपाल में स्थानीय मुखबिरों की मदद से फर्जी शादी गिरोह से संपर्क किया। टीम के एक सिपाही को अविवाहित बताकर फर्जी शादी कराने की योजना बनाई गई।

जल गंगा संवर्धन अभियान में राजगढ़ ने किया कमाल

जिला जल संवर्धन कार्यों में प्रथम स्थान पर, ओवर-ऑल 8.51 रैंकिंग

भोपाल। जल गंगा संवर्धन अभियान में जल संरचनाओं के प्रदेश में सर्वाधिक निर्माण पूरा करने पर राजगढ़ जिले को अब तक 25 में से 8.51 अंक प्राप्त हुए हैं। जिला अब तक प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जल गंगा संवर्धन अभियान में राजगढ़ जिले में अमृत सरोवर लक्ष्य से अधिक और प्रदेश में सर्वाधिक कार्य प्रारंभ कराए गए हैं। इसी तरह जिला खेत तालाब भी लक्ष्य से अधिक प्रारंभ कराने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इस तरह जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए My Bharat पोर्टल पर युवाओं का रजिस्ट्रेशन भी राजगढ़ ने लक्ष्य 5,400 से अधिक 10,186 से अधिक कार्य कराए हैं। प्रदेश स्तर रैंकिंग में जिले को अब तक 8.51 रैंकिंग अंक मिले हैं। इस तरह अब तक राजगढ़ प्रदेश में अव्वल है। राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जिले में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे जल संवर्धन के कार्यों में मनरेगा योजना में कुल 18 अमृत सरोवर तालाब निर्माण का लक्ष्य शासन से प्राप्त हुआ है। लक्ष्य अनुसार सभी 19 तालाबों के लिए स्थल चयन SIPRI ऐप से किया जाकर भारत सरकार के अमृत सरोवर पोर्टल पर उसकी प्रविष्टि कराई जा चुकी है। इन सभी अमृत सरोवरों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। मनरेगा योजनान्तर्गत जल संरक्षण के लिये कुल 1866 खेत तालाब के लक्ष्य से अधिक 1989 खेत तालाबों के स्थल चयन एसआईपीआरआई मोबाइल ऐप से फायनल कर निर्माण प्रारंभ किये जा चुके हैं। मनरेगा योजनान्तर्गत जल संरक्षण के लिये कुल 3,500 कूप रिचार्ज निर्माण के लक्ष्य से अधिक 3600 कूपों का चयन कर 3165 पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। अभियान अंतर्गत कूप रिचार्ज लक्ष्य 3500 के विरुद्ध 3165 कूप रिचार्ज के कार्य प्रारंभ करने पर प्रदेश स्तर पर हो रही रैंकिंग में 20 में से अब तक 18 अंक प्राप्त हुए हैं। जिला खेत तालाब कार्य प्रारंभ करने में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है।

बोरी बंधान से 12 घंटे में मुड़ना नदी हुई लबालब

शहडोल में सोहागपुर के जोधपुर गांव से बहने वाली मुड़ना नदी की जलधारा सूख सी गई थी। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत श्मशान घाट के पास पहले से निर्मित स्टॉप-डैम में जन-अभियान परिषद की जोधपुर समिति और ग्राम पंचायत ने इसी स्टॉप-डैम में बोरी बंधान का निर्माण किया। श्रमदानसे हुए बोरी बंधान से धीरे-धीरे मुड़ना नदी के बहाव क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने लगा। श्रमदान दिवस के बाद की सुबह नदी को लबालब देख गांव के पशु-पक्षियों तक में खुशी की लहर दौड़ गई। अब नदी में पेयजल के साथ ही सबके लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया है। देवास जिले में 'जल गंगा संवर्धन अभियान'चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं। जल की प्रत्येक बूंद को सहेजने के लिए 30 जून 2025 तक ये अभियान जारी रहेगा। जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में नगर निगम देवास के राजोदा स्थित मीठा तालाब की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। तालाब के किनारे पौधारोपण भी किया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उमरिया जिले की नगर परिषद मानपुर में भंडारी नदी में बोरी बंधान किया गया। बोरी बंधान से नदी में जल संग्रह की क्षमता बढ़ गई है और पर्याप्त मात्रा में पानी रुकने लगा है। बोरी बंधान से नदीं में सहरेजे गए पानी का उपयोग पशु पक्षियों के साथ आम जन भी कर सकेंगे।

बहन की मौत के बाद बाघिन ने पाले उसके बच्चे

अब छोड़े शावक, एमपी में पहली बार हुई ऐसी घटना, चार साल तक पाला, शिकार करना सिखाया, अब छोड़ा

भोपाल। सीधी जिले के संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में एक अनोखी घटना सामने आई है। बाघिन टी28, जिसे 'मौसी' के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी बहन के तीन शावकों को चार साल तक पाला। बहन की मौत के बाद उसने उन्हें शिकार करना सिखाया और अब उन्हें खुद से अलग कर दिया है। यह एमपी में ऐसा पहला मामला है। 19 मई को शावक बाघिन से अलग दिखाई दिए। डीएफओ राजेश कन्ना टी और टमसार रेंजर असीम भूरिया के अनुसार, बाघिन ने अपनी बहन 'कमली' के शावकों को भी पाला था। इस असाधारण व्यवहार के कारण उसे मौसी, सुपर मॉम और आइकॉनिक मॉम जैसे नामों से जाना जाने लगा। 16 मार्च 2021 को संजय टाइगर रिजर्व के दुबरी रेंज में एक दुखद घटना हुई। एक बाघिन, जिसका नाम कमली (टी18) था, ट्रेन से टकराकर घायल हो गई। वह लगभग 9 महीने पहले चार नर शावकों को जन्म दे चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने कमली को बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कमली के चार शावक जंगल में अनाथ हो गए। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने उनकी देखभाल शुरू की। 24 घंटे गश्त के लिए वन अमले की ड्यूटी लगाई गई। शावकों को भोजन मुहैया कराया गया। जिस

क्षेत्र में शावक रहते थे, वहां एक वयस्क बाघ टी-26 भी था। उसने चार में से एक शावक को मार डाला। यह दुखद था कि शावक को मारने वाला बाघ भी कमली का ही बच्चा था। इसके बाद कमली के तीन शावक बचे थे। कमली और टी28 (मौसी) सगी बहनें थीं। कमली को पहली बार जून 2020 में शावकों के साथ देखा गया था। टी28 ने भी अक्टूबर-नवंबर 2020 के आसपास तीन शावकों को जन्म दिया था। दोनों की मां टी11 थी। दोनों की टैरेटरी अलग-अलग थी, लेकिन कमली की मौत के बाद एक अजीब घटना देखने को मिली। कमली की मौत के कुछ दिन बाद टी28 के तीनों शावकों के साथ कमली के तीन शावक नजर आने लगे। टाइगर रिजर्व के गश्ती दल ने देखा कि बाघिन मौसी, कमली के शावकों का ध्यान अपने शावकों की तरह रख रही है। वह उनकी निगरानी कर रही थी और उनके लिए शिकार का इंतजाम भी कर रही थी। उन्हें शिकार करना भी सिखा रही थी। कुछ दिन बाद टी28 के एक शावक की भी हादसे में मौत हो गई। इसके बाद वह पांचों शावकों की देखभाल करने लगी। आमतौर पर बाघ-बाघिन अपने शिकार में किसी दूसरे की हिस्सेदारी पसंद नहीं करते, लेकिन इस बाघिन ने ऐतराज नहीं जताया। टी28 का इलाका टाइगर रिजर्व के मध्यवर्ती और पश्चिमी हिस्सों में फैला है। यह बाघिन अपनी ममता के साथ-साथ अपने शिकारी कौशल के लिए भी जानी जाती है। अप्रैल 2025 में इसने एक सांभर का शिकार किया। उसे अपने बच्चों के लिए जंगल में ले गई। सभी ने मिलकर शिकार खाया। टी28 ने अब तक 8 शावकों को पाला है। पांच अपने और तीन अपनी बहन के। किसी भी टाइगर रिजर्व में अपने आप में इस तरह का ये पहला मामला है। बाघ अकेला रहने वाला जानवर है। अपनी टैरेटरी में किसी और को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन टी28 ने न केवल अपने शावकों को एकजुट रखा बल्कि अपनी बहन के बच्चों को भी परिवार का हिस्सा बनाया। 19 मई को एक वीडियो सामने आया, जिसमें चारों शावक अलग-अलग दिख रहे हैं। इससे पता चलता है कि मौसी बाघिन ने शावकों को छोड़ दिया है।

संपादकीय

मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी: अच्छी पहल

मप्र के पांच बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की सौगात देना मोहन यादव का बड़ा, दूरदर्शी और सराहनीय फैसला है। इससे राज्य के पांच प्रमुख शहरों के बहुआयामी विकास को पंख लगेंगे। इन पांच में से भी दो सबसे अहम भोपाल और इंदौर को इस तरह की योजना की तुरंत आवश्यकता थी, क्योंकि इन दोनों शहरों का विकास चौतरफा और बहुत तेजी से हो रहा है। मोहन यादव मंत्रिमंडल ने देवी अहिल्या की नगरी इंदौर के ऐतिहासिक राजबाड़ा में आयोजित कैबिनेट की विशेष बैठक में इस अधिनियम को मंजूरी दी। इसका नाम मप्र मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 (एक्ट) है। इसके तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी (प्राधिकरण) बनाई जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरी क्षेत्र भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने की शुरुआत होगी। उल्लेखनीय है कि भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में 9600 वर्ग किमी और इंदौर रीजन में करीब 10 हजार वर्ग किमी क्षेत्र शामिल होगा। दोनों क्षेत्रों के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी (एमपीसी) व मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमआरडीए) का गठन होगा। यह सवाल प्रदेश के नागरिकों के मन में उठना स्वाभाविक है कि इस तरह के मेट्रोपॉलिटन रीजन की जरूरत क्यों पड़ी, इससे क्या बदलेगा और आम लोगों को क्या फायदा होगा। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इंदौर और भोपाल शहरों का विकास तेजी से हो रहा है। जैसे-जैसे शहर का दायरा बढ़ रहा है उसके हिसाब से प्लानिंग जरूरी है। शहरी और ग्रामीण विकास के लिए एकीकृत और समन्वित प्रयासों की जरूरत है। अगर भोपाल की ही बात की जाए तो प्रदेश की इस राजधानी का मास्टर प्लान आज तक मंजूर नहीं हुआ। कब होगा कोई नहीं जानता। संभव है कि मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनने के बाद इसमें कुछ तेजी और सुधार आए। नई अथॉरिटी से यह भी अपेक्षा है कि वह सम्बन्धित शहरों के विकास की क्षमताओं के आधार पर भूमि उपयोग का निर्धारण करने और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों और शहरों के एकीकृत विकास की योजना पर अमल करे। एक्ट के अंतर्गत इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में पांच जिलों इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर को शामिल किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 9 हजार वर्ग किमी का है। इसकी वर्तमान आबादी 55 लाख के करीब होगी, मगर इसे 75 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर रीजन विकसित किया जाएगा। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) इसकी नोडल एजेंसी होगा। इसकी एक वजह 2028 में उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ समागम भी है। साथ ही इसमें दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी जोड़ा गया है। सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों और व्यापार को नई गति मिलेगी। इसी तरह भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया में भोपाल- सीहोर-रायसेन-विदिशा और राजगढ़ जिले के ब्यावरा को शामिल किया गया है। भोपाल विकास प्राधिकरण को मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलप करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। इन पांचों जिलों को मिलाकर भोपाल रीजन का कुल क्षेत्रफल 9600 वर्ग किमी होगा। 14 माह में इन जिलों का सर्वे कर रीजनल डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट प्लान बनेगा। भोपाल रीजन दक्षिण में औबेदुल्लागंज और उत्तर में श्यामपुर व आष्टा तक हो जाएगा। पूरा प्लान 60 लाख की संभावित आबादी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन रीजन एरियाको 4 चरणों में डेवलप किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें इंस्पेक्शन, सिचुएशन एनालिसिस, रीजनल एवं इन्वेस्टमेंट प्लान और डीपीआर शामिल है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद एक्ट का बिल जुलाई में संभावित मानसून सत्र में पेश होगा। विधानसभा से अधिनियम को मंजूरी मिलने के बाद महानगर विकास प्राधिकरण (मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी) का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। योजना अच्छी है, जमीन पर कैसे अमल में आती है, इस पर इसका भविष्य निर्भर है।

सूचना क्रांति के दौर में गांधी की धीमी पत्रकारिता की प्रासंगिकता

नजरिया

सोपान जोशी

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

न्यायालय में भारतीय व्यापारियों की तरफ से जिरह कर-करके मोहनदास को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की करीबी समझ होने लगी थी। आमतौर पर वकील केवल अपने मुवक्किल की बात करते हैं, लेकिन मोहनदास को वकालत के संबंध बहुत संकरे लगने लगे थे। उन्हें अपना दायरा बढ़ाना था और ज्यादा लोगों से बात करनी थी। इसके लिए उन्हें एक ही रास्ता दिखा - पत्रकारिता। इस छापाखाने से मोहनदास के संपादन में 'इंडियन ओपिनियन' नामक एक पत्र निकलने लगा। वकालत की औपचारिक शिक्षा पाए मोहनदास ने अनौपचारिक और व्यावहारिक तरीके से पत्रकारिता सीखी। वे छापने लायक सामग्री इकट्ठा करते, उसकी छंटाई करते और उसे इस तरह से लिखते कि वह पढ़ने वालों में विचार का संचार करे। सत्य को गहराई से समझने की आदत डाले। उनकी लिखाई साफ-सुथरी थी और छपाई में सादापन था। कागज और छपाई के खर्च उन्हें महँगे पड़ते थे और धन की कमी सदा ही रहती थी। इसलिए संपादक गांधी का जोर रहता था कि कम-से-कम शब्दों में ज्यादा-से-ज्यादा बात हो। एक वकील अब एक मंजा हुआ पत्रकार बन चला था।

आज जानकारी उपनिवेश और साम्राज्य की गति से भी अधिक तेजी से दौड़ती है। इस सूचना क्रांति के बारे में कहा जाता है कि इसने साधारण लोगों का सशक्तिकरण किया है। इसकी बात नहीं होती कि सूचना की यह बिजली की गति लोगों को दास बनाकर एक मशीनी भ्रांति में रखने की गजब की ताकत भी रखती है। गांधीजी के लिखे में पाठकों को सब्र के साथ पढ़ने के निर्देश बार-बार आते थे। वे पाठक को धीमे-धीमे और कई बार पढ़ने को कहते थे। वे मानते थे कि उनके हर आदर्श पाठक में स्वाध्याय और सत्याग्रह की योग्यता है।

आइये, इसे समझने के लिए किसी और देश काल में चलते हैं। 29 नवंबर 1898, दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर। इस दिन एक छापाखाना खुला था। इसके उद्घाटन समारोह में लगभग 100 लोग आए थे। मदन जीत नामक एक शिक्षक ने इसका खर्च उठाया था।

अब्दुल कादिर नाम के एक व्यापारी ने प्रेस लगाने के लिए बिना किराए की जमीन दी थी। असल में इस छापाखाने के पीछे 29 साल के युवा वकील मोहनदास करमचंद गांधी का हाथ था।

न्यायालय में भारतीय व्यापारियों की तरफ से जिरह कर-करके मोहनदास को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की करीबी समझ होने लगी थी। आमतौर पर वकील केवल अपने मुवक्किल की बात करते हैं, लेकिन मोहनदास को वकालत के संबंध बहुत संकरे लगने लगे थे। उन्हें अपना दायरा बढ़ाना था और ज्यादा लोगों से बात करनी थी। इसके लिए उन्हें एक ही रास्ता दिखा - पत्रकारिता।

इस छापाखाने से मोहनदास के संपादन में 'इंडियन ओपिनियन' नामक एक पत्र निकलने लगा। वकालत की औपचारिक शिक्षा पाए मोहनदास ने अनौपचारिक और व्यावहारिक तरीके से पत्रकारिता सीखी। वे छापने लायक सामग्री इकट्ठा करते, उसकी छंटाई करते और उसे इस तरह से लिखते कि वह पढ़ने वालों में विचार का संचार करे। सत्य को गहराई से समझने की आदत डाले। उनकी लिखाई साफ-सुथरी थी और छपाई में सादापन था। कागज और छपाई के खर्च उन्हें महँगे पड़ते थे और धन की कमी सदा ही रहती थी। इसलिए संपादक गांधी का जोर रहता था कि कम-से-कम शब्दों में ज्यादा-से-ज्यादा बात हो। एक वकील अब एक मंजा हुआ पत्रकार बन चला था।

यह पत्रकार जानकारी और गुलामी का संबंध भी समझने लगा था। वे यह जानने लगे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य और उसकी शोषण की विशाल व्यवस्था तेज गति से जानकारी के लेन-देन पर टिकी हुई थी। साम्राज्य चलाने के लिए अँग्रेज हुक्मरानों को यह मालूम रखना जरूरी था कि कब, कहाँ, क्या हो

रहा है। इस तेजी से चलती जानकारी के बिना साम्राज्य की सैन्य ताकत, पूंजीवाद की हवस और औद्योगिक मशीनों की शक्ति बेकार थी।

तब दक्षिण अफ्रीका में एक स्वतंत्र विचार का अखबार निकालना आसान नहीं था। खासकर जब भारतीय लोगों की समस्याओं पर सामाजिक आंदोलन भी खड़ा किया जा चुका हो। गांधीजी पर अध्ययन करने वाले कई लोग मानते हैं कि 1906 से 1909 के बीच का समय उनके लिए भारी उथल-पुथल का था। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह थम गया था। जनरल स्मट्स के साथ किया समझौता गांधीजी को भारी लगने लगा था। धंधे में नुकसान के डर से धनी व्यापारी गांधीजी का साथ छोड़ चले थे। अब उनके समर्थकों में गरीब तबके के लोग ही ज्यादा रह गये थे।

गांधीजी अंतर्मुखी हो चले थे। उनका ध्यान सत्याग्रह के राजनीतिक पक्ष की बजाय, उसके अध्यात्मिक वजन पर जाने लगा था। वे साधारण लोगों में चेतना और विवेक चाहते थे, ताकि वे साम्राज्यवाद और औद्योगिक व्यवस्था से होने वाली मशीनी दुर्गति से बच सकें। उन्हें एक ही उपाय सूझा। जानकारी, सूचना और समझ की इस रफ़्तार को धीमा करने की जरूरत थी। पढ़ना-समझना मनुष्य के शरीर और मन की प्राकृतिक गति से क्यों न हो? उन्हें लगने लगा था कि पढ़ना, लिखना और संपादन, तीनों ही क्रियाएं ध्यान से और सोच-समझकर होनी चाहिए, हड़बड़ी और उतावली में नहीं।

पाठकों में यह बदलाव कैसे आए? इसका एक अद्भुत वृत्तांत मिलता है, 2013 में छपी एक अँग्रेजी किताब 'गांधीज प्रिंटिंग प्रेसः एक्सपैरिमेंट्स इन स्लो रीडिंग' में। किताब की लेखक हैं, अफ्रीकी साहित्य की प्राध्यापक इसाबेल हॉफ्मायर, जिन्होंने नए सिरे से पुराने दस्तावेजों को खंगाला है। उनकी किताब पत्रकारिता पर एक ऐतिहासिक नजर तो डालती ही है, हमारे आज के हालात में तो वह और भी आवश्यक है।

आज जानकारी अधिक तेजी से दौड़ती है। इस सूचना क्रांति के बारे में कहा जाता है कि इसने साधारण लोगों का सशक्तिकरण किया है। इसकी बात नहीं होती कि सूचना की यह बिजली की गति लोगों को दास बनाकर एक मशीनी भ्रांति में रखने की गजब की ताकत भी रखती है। सोशल मीडिया, टीवी न्यूज़ चैनल और स्मार्ट फोन बिजली की तेजी से लोगों को बरगलाने में सक्षम हैं। साधारण लोगों को एक क्रुद्ध और जानलेवा भीड़ में तब्दील कर देना इतना आसान पहले कभी नहीं रहा। स्मार्ट फोन में 'इंस्टॉल' करने के लिए विवेक और समझदारी का कोई 'ऐप' नहीं है।

ऐसे में गांधी जी के प्रयोग को याद करने की जरूरत है। थोड़ी धीमी गति से, नैसर्गिक गति से भी पत्रकारिता की जा सकती है, जो लोगों में विचार का संचार करे। इसाबेल की किताब विस्तार से बताती है कि गांधीजी ने अपने पाठकों को खुद तैयार किया था। वे संपादन की समस्याएं भी खुलकर बताते थे। एक जगह उन्होंने लिखा है कि संपादन करते समय उन्हें अपनी कमजोरियां और साफ दिखती हैं। कभी तो आत्मलीन होकर लच्छेदार भाषा में लिखने का मन होता है। फिर ऐसा भी लगता है कि अपने क्रोध के वश में आकर सारा जहर शब्दों में उगल दें, लेकिन उनकी कोशिश यही रहती थी कि संयम से काम लें, लिखाई में विवेक का सहारा लें।

ऐसा नहीं था कि पाठक से उनका संबंध किसी प्रचारक का रहा हो, जिसका जीवन वे अपनी विचारधारा के हिसाब से बदल देना चाहते थे। पाठक उनके लिए वह ग्राहक भी नहीं था, जिसकी आँख से होते हुए सीधे उसकी जेब पर निशाना साधा जाए। गांधी जी अपने पाठक के साथ बेबाक रिश्तेदारी और अधिकार रखते थे। वे यह भी लगातार कहते थे कि संपादक और मालिक से ज्यादा किसी प्रकाशन की मिल्कियत उसके पाठकों में होती है। पाठकों के पत्रों का जवाब वे ऐसे देते थे, जैसे किसी निकट के संबंधी से बात कर रहे हों।

इस पत्रकारिता में एक विशाल और सदाचारी सामाजिक जीवन के बीज थे। धीरे-धीरे इससे एक ऊँचा और बड़ा पेड़ निकला, जिसकी शीतल छाया में हम आज भी बैठ सकते हैं। चाहे उसमें बैठे हुए हम बिजली की तेजी से अपने स्मार्ट फोन पर किसी और को बिला वजह गालियां ही क्यूँ न दे रहे हों। (सप्रेस)

देश के आइकन्स को ट्रोल करने की यह कैसी सोच?

सरकार का कर्तव्य

राजीव खंडेलवाल

(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व बैतूल सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 एक नागरिक को ''जीने के अधिकार'' प्रदान करता है। उस अधिकार में 'मानवीय गरिमा' के साथ मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण तथा जीने योग्य बनाने वाले समस्त पहलू शामिल हैं। अतः देश का संविधान निःसंदेह प्रत्येक नागरिक को 'सम्मान से जीने का अधिकार' देता है, जिसकी रक्षा का दायित्व कार्यपालिका व न्यायपालिका पर है। फलतः संविधान किसी भी व्यक्ति को एक नागरिक के सम्मान पर जाति, धर्म के आधार पर चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है। यह सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों के जीने अधिकार की रक्षा कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने देने की परिस्थितियां निर्मित सुनिश्चित करें। तदनुसार प्रत्येक नागरिक को 'असम्मान के कटघरे के घेरे से सुरक्षा प्रदान करें।' हालांकि 'ख़लक का हलक़ किसी ने बंद नहीं किया है' लेकिन जो देश के 'फलक़' पर गंदी इबारतें लिख उसका सम्मान घटाये, उसे संविधान की ''हनक'' दिखानी भी जरूरी है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, शहीद नरवाल की विधवा हिमांशी नरवाल, लखनऊ विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. माद्री काकोटी, भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर जैसे 'आईकॉन' व प्रतिष्ठित नागरिक हों, जिनको बेशर्मी के साथ सोशल मीडिया पर निम्न से निम्नतम स्तर पर जाकर चारित्रिक हनन करके बेरोक-टोक ट्रोल किया जा रहा हो और सरकार है कि 'खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं'' की मुद्रा में हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है। जिस प्रकार चुप रहना ''सहमति'' मानी जाती है, जिसे कहते हैं 'खामोशी नीम रजा', उसी प्रकार 'कुछ कार्रवाई न करना' भी क्या उक्त ट्रोलिंग टीम के लिए सरकार की ''सहमति'' मानी जाए? यानी कि ''सैंया भए कोतवाल तो फिर.......''।

संघर्ष विराम का निर्णय सरकार का! फिर सेना व सरकार के अधिकारियों को ट्रोल क्यों।

आईये! कुछ प्रकरणों का अध्ययन करें व स्थिति समझने का प्रयास करें। ''ऑपरेशन सिंदूर'' के प्रारंभ होते ही संघर्ष विराम तक सेना की लगातार तीन दिन व उसके बाद भी ''प्रेस ब्रीफिंग'' विदेश सचिव विक्रम मिसरी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, नपे तुले शब्दों में प्रभावी रूप से कर रही थी। भारत सरकार इस टीम को सामने लाकर देश की सांप्रदायिक सद्भावना को भंग करने के पाकिस्तान के कुत्सित प्रयासों के जवाब का एक 'सांकेतिक संदेश' भी सफलतापूर्वक दे रही थी। इस देश में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर खूब सराहा भी गया। परन्तु अचानक भारतीय सेना की जीत की अवस्था, स्थिति के समय पर अप्रत्याशित ''संघर्ष विराम'' की घोषणा होने के कुछ समय पश्चात ही सोशल मीडिया पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी व कर्नल सोफिया को अपमानित कर बुरी तरह से ट्रोल किया जाने लगा। जबकि वस्तुतः वे संघर्ष विराम की जानकारी देते समय भारत सरकार व सेना का एक अंग होकर मात्र अपना कर्तव्य निभा रहे थे। 'संघर्ष विराम' का निर्णय विदेश सचिव या कर्नल सोफिया कुरैशी या सेना के स्तर पर न होकर राजनैतिक स्तर पर हुआ था। परंतु दुर्भाग्यवश इसकी जानकारी भारत सहित संपूर्ण विश्व को सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व तत्पश्चात भारत सरकार ने दी, जिसने पूरे परिदृश्य, परसेप्शन को ही बदल दिया।

अचानक हतप्रभ करने वाले संघर्ष विराम के निर्णय को देश के बड़े भाग में जनता ने पसंद नहीं किया। शायद इसका ही परिणाम था कि ''संघर्ष विराम'' को लेकर सोशल मीडिया में बेहद बुरी तरीके से प्रेस ब्रीफिंग टीम को ट्रोल किया जाने लगा। यद्यपि संघर्ष विराम की घोषणा तो भारत सरकार का निर्णय था, जिनको ट्रोल किया जाना चाहिए था? तथापि शायद वहां तक पहुंचने की ताकत व क्षमता उक्त ट्रोल आर्मी की नहीं थी। अथवा वे उसे दिशा में जाना ही नहीं चाहते थे? या फिर इनके भीतर बैठा ''अभद्रताजीवी बेताल सवार होने के लिये आसान कंधे की तलाश में था''। इसलिए उनके प्रतीक, प्रतिनिधि के रूप में विक्रम मिस्त्री, कर्नल सोफिया कुरैशी को ट्रोल किया गया। यदि सिर्फ ''युद्धविराम के निर्णय'' तक ट्रोल को सीमित रखा जाता, तो भी ठीक था। परन्तु दुर्भाग्य यह था कि पूर्ण रूप से अत्यंत शर्मनाक तरीके से कर्नल पर व्यक्तिगत अभद्र, गंदी टिप्पणियां किये जाने के बावजूद उनके सम्मान को बचाने के लिए भारत सरकार ने इन ट्रोल आर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय विदेश सचिव ने तो अपना ट्वीटर हेंडल को मजबूरन ''निजी'' ही कर लिया। परन्तु सरकार ने मजबूर करने वाले के विरूद्ध एक कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत इसके सरकार और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर प्रश्न करने वालों के विरुद्ध कई राज्यों की सरकारों ने कार्रवाई की है।

ताजा उदाहरण सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान मोहम्मदाबाद का है, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में एक पोस्ट ''फेसबुक'' में डालने पर हरियाणा की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इनका भी गौरवशाली इतिहास रहा है। सोशल मीडिया में चल रहे इन ट्रोल आर्मी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और न ही उनके खिलाफ सरकार व भाजपा के प्रमुख नेताओं ने बयान जारी कर कार्रवाई की मांग की। देश के नागरिकों से लेकर समस्त पार्टियां, अत्यधिक सम्मानित सेना के अधिकारियों व सेना की पूजा, नमन पूरा देश कर रही हो, तब उनके आन-बान-शान के खिलाफ कहे गए शब्दों के विरूद्ध कार्रवाई न करना का मतलब एक ही निकलता है कि हर एक चीज में वोट की राजनीति को देखा जाता है। साफ है कि ''ये बछड़े किस खूंटे के बल पर कूद रहे हैं''।

महिला अधिकारों के लिए लड़ती रही हैं बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक़

शेरिलान मोलान

भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक़ ने लघु कथा संकलन, 'हार्ट लैंप' के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। कन्नड़ भाषा में लिखी गई यह पहली किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ है। 'हार्ट लैंप' की कहानियों का अंग्रेज़ी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है।

1990 से 2023 के बीच मुश्ताक़ की लिखी 12 लघु कथाओं वाली किताब 'हार्ट लैंप' में, दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलों का बहुत मार्मिक चित्रण किया गया है। मुश्ताक़ को मिला पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ़ उनके काम को ही रेखांकित नहीं करता बल्कि भारत की संपन्न क्षेत्रीय साहित्यिक परंपरा को भी दर्शाता है।

इससे पहले साल 2022 में गीतांजलि श्री की पुस्तक 'टॉम्ब ऑफ़ सैंड' को ये पुरस्कार मिला था। 'टॉम्ब ऑफ़ सैंड' का हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद डेज़ी रॉकवेल ने किया था। पुस्तक प्रेमियों के बीच बानू मुश्ताक़ की लेखनी चिर-परिचित है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर अवार्ड ने उनकी ज़िंदगी और साहित्य को दुनिया के सामने पेश किया है।

उनका साहित्य महिलाओं के सामने आने वाली उन चुनौतियों की झलक देता है जो धार्मिक संकीर्णता और पितृसत्तात्मक समाज से पैदा हुई हैं। यह उनकी अपनी जागरूकता ही है जिसने शायद मुश्ताक़ को बारीक चरित्र और कथानक गढ़ने में मदद की। इस किताब के बारे में 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपे रिव्यू में लिखा गया है, 'जहां साहित्य में अक्सर बड़े कथानक को पुरस्कृत किया जाता है, वहीं हार्ट लैंप हाशिए पर ज़िंदगियों के बारे में है। ये किताब टिकी है अनदेखे विकल्पों के बारे में बारीक़ नज़र पर। और यही उसकी ताक़त है। यही बानू मुश्ताक़ की ख़ामोश ताक़त है।'

मुश्ताक़ कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में मुस्लिम इलाके में पली-बढ़ीं और अपने आसपास की अधिकांश लड़कियों की तरह उन्होंने भी स्कूल में उर्दू भाषा में क़ुरान का अध्ययन किया। लेकिन सरकारी कर्मचारी रहे उनके पिता चाहते थे कि बानू मुश्ताक़ आम स्कूल में पढ़ें। जब वह आठ साल की थीं, तब उनके पिता ने उनका दाख़िला एक कॉन्वेंट स्कूल में करवाया जहां कन्नड़ भाषा में पढ़ाई होती थी। मुश्ताक़ ने कन्नड़ भाषा में माहिर होने के लिए कड़ी मेहनत की। बाद में यही भाषा उनकी साहित्यिक अभिव्यक्ति की भाषा बन गई।

स्कूल के समय से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जब उनकी सहेलियां शादी करने लगीं तो बानू मुश्ताक़ ने कॉलेज जाने का विकल्प चुना। मुश्ताक़ का लेखन छपने में सालों लगे और यह तब हुआ जब वह ख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी के सबसे चुनौतीपूर्ण पलों से गुजर रही थीं।

26 साल की उम्र में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी के एक साल बाद उनकी लघु कथा एक स्थानीय मैग्ज़ीन में छपी, लेकिन उनका शुरुआती विवाहित जीवन संघर्षों और कलह

वाला रहा। इस बारे में उन्होंने कई बार खुलकर बात की है। वोग मैग्ज़ीन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'मैं हमेशा से लिखना चाहती थी लेकिन कुछ लिखने को नहीं था। फिर लव मैरिज के बाद अचानक मुझे बुरक़ा पहनने को कहा गया और पूरी ज़िंदगी घरेलू काम में लगाने को कहा गया। 29 साल की उम्र में मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से पीड़ित मां बन गई।'

'द वीक' मैग्ज़ीन को दिए एक अन्य इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी ज़िंदगी घर के अंदर बंध कर रह गई थी। इसके बाद, एक चौंकाने वाले विद्रोह ने बानू मुश्ताक़ को मुक्त कर दिया। उन्होंने पत्रिका को बताया, 'एक बार बहुत निराशा के पलों में मैंने खुद को आग लगाने के लिए अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया था। शुक्र है कि मेरे पति समय रहते भांप गए। उन्होंने मुझे गले लगाया और माचिस दूर फेंक दी। फिर मेरे पांव में बच्चे को रख कर मिन्नत की कि हमें मत छोड़ो।'

'हार्ट लैंप' में उनकी महिला किरदार प्रतिरोध और विद्रोह के इसी जज़्बे को प्रतिबिंबित करती हैं।

'इंडियन एक्सप्रेस' अख़बार में छपे एक रिव्यू के अनुसार, 'मुख्य धारा के भारतीय साहित्य में, मुस्लिम महिलाओं को अक्सर एक जैसे सपाट रूपकों में ढाल दिया जाता है। मुश्ताक़ ने इसे ख़ारिज किया। उनके किरदार मेहनती हैं, मोलभाव करते हैं और कभी कभी विरोध भी दर्ज करते हैं। ये विरोध वैसा नहीं है जिससे सुर्ख़ियां बनें बल्कि ऐसा है जिससे उनकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़े।'

लेकिन उनकी तीखी लेखनी ने उन्हें नफ़रत के निशाने पर भी ला दिया। 'द हिंदू' अख़बार में दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि कैसे साल 2000 में उन्हें धमकी भरे फ़ोन आए थे क्योंकि उन्होंने मस्जिदों में नमाज पढ़ने के महिला अधिकारों के समर्थन में अपने विचार प्रकट किए थे। उनके ख़िलाफ़ फ़तवा जारी किया गया और एक व्यक्ति ने उनपर चाकू से हमला करने की कोशिश की, हालांकि उनके पति ने उसे दबोच लिया।

लेकिन इन घटनाओं से मुश्ताक़ डरी नहीं और उन्होंने ईमानदारी से लिखना जारी रखा।

'द वीक' मैग्ज़ीन को उन्होंने बताया था, 'मैंने हमेशा अंधश्रद्धा वाली धार्मिक व्याख्याओं को चुनौती दी है। ये मुद्दे मेरे लेखन के केंद्र में रहे हैं. समाज बहुत बदल गया है, लेकिन बुनियादी मुद्दे अभी भी वही। भले ही संदर्भ बदल रहा हो- लेकिन महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों का बुनियादी संघर्ष जारी हैं।'

पिछले कुछ सालों में मुश्ताक़ के लेखन को कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और दाना चिंतामणि अत्तिमाबे पुरस्कार समेत कई प्रतिष्ठित स्थानीय और राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। 2024 में, 1990 और 2012 के बीच प्रकाशित मुश्ताक़ की पांच लघु कहानी संग्रहों के अनूदित अंग्रेजी संकलन, 'हसीना एंड अदर स्टोरीज' ने प्रतिष्ठित 'पेन ट्रांसलेशन प्राइज' भी जीता था।

(बीबीसी हिंदी से साभार)

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

शादी : रिश्तेदारों का तड़कता-भड़कता रियलिटी शो

व्यंग्य

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

लेखक व्यंग्यकार हैं।

भारतीय शादी महज एक समारोह नहीं, बल्कि एक जीवंत, रंग-बिरंगा रियलिटी शो है, जिसमें ड्रामा, कॉमेडी, और सस्पेंस की कोई कमी नहीं। दूल्हा-दुल्हन भले ही मंच के केंद्र में हों, लेकिन असली सितारे तो हमारे रिश्तेदार हैं। ये वो अनोखे किरदार हैं, जो बिन बुलाए समीक्षक, बिना डिग्री के जासूस, और बिना माइक के धमाकेदार कमेंटेटर बनकर हर पल में जान डाल देते हैं। इनके पास हर मौके पर तीखी टिप्पणी का अनलिमिटेड लाइसेंस और हर छोटी-बड़ी बात को तूल देने का हुनर होता है।

जैसे ही शादी का कार्ड हाथ में आता है, रिश्तेदारों का छिपा हुआ जीपीएस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, जो गूगल मैप को भी मात दे देता है। अरे, ये वही मैरियट होटल तो नहीं, जहाँ सक्सेना जी की बेटी की शादी में पंडाल का तंबू टपक रहा था? ये कोई सवाल नहीं, बल्कि एक जासूसी मिशन का शंखनाद है! ये लोग जगह की भौगोलिक स्थिति कम, सामाजिक स्टेटस की गहराई ज्यादा नापते हैं। ये शादी के वेन्यू को ऐसे स्कैन करते हैं, जैसे नासा चाँद पर खजाना ढूंढ रहा हो। इनके लिए शादी की लोकेशन सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि सामाजिक रुतबे का चमकता बैरोमीटर है, जो हर छोटी बात को स्टेटस की कसौटी पर कसता है।

रिश्तेदारों की नजरें किसी अल्ट्रा-एचडी सीसीटीवी कैमरे से कम नहीं - हर डिटेल पर इनका लेंस फोकस्ड रहता है। जैसे ही दुल्हन स्टेज पर कदम रखती है, इनका 'हाई-जूम मोड' तुरंत ऑन हो जाता है। लहंगे का बॉर्डर असली जरी का है या सस्ता गोटा? जरा करीब से तो देखें। ये लहंगा तो ऑनलाइन लिया होगा, बिलकुल बारीक काम नहीं। दूल्हे की शेरवानी भी इनके तीक्ष्ण रडार से नहीं बचती। अरे, वो कॉलर की कढ़ाई देखो, मशीन की है, हैंडमेड तो बिलकुल नहीं। ये लोग मेहमानों की भीड़ में भी हर चेहरे को स्कैन करने में माहिर हैं। इनके लिए शादी का हर कोना एक रहस्यमयी क्राइम सीन है, और ये खुद को शेरलॉक होम्स से कम नहीं मानते।

रिश्तेदारों की गपशप फैक्ट्री किसी 24×7 न्यूज़ चैनल से कम नहीं - हर पल एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ तैयार। सुना है, पंडित जी ने मंत्र में चूक कर दी। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक स्टोरीज में ऐसी गॉसिप की सुनामी लाते हैं कि बड़े-बड़े न्यूज़ नेटवर्क भी हैरान रह जाएं। अगर किसी ने रिसेप्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर न डालीं, तो तुरंत कानाफूसी शुरू - कुछ तो गड़बड़ है, भाई। गिफ्ट्स खोलने का वक्त आते ही इनका लाइव स्टूडियो ऑन हो जाता है - वो लाल लिफाफा देखा? सिर्फ 251 रुपये। हर शादी इनके लिए किसी धमाकेदार वेब सीरीज का नया एपिसोड है, जहाँ टीआरपी की भूख कभी शांत नहीं होती।

अगर आप शादी में सिंगल हैं, तो रिश्तेदारों का 'अब तेरी बारी' दस्ता तुरंत आपके पीछे पड़ जाता है, मानो आप कोई हाई-प्रोफाइल मिशन हो। इनका बायोडाटा स्कैनिंग सिस्टम किसी डेटिंग ऐप से कहीं ज्यादा तेज और तीखा है। बेटा, अब तो उम्र निकल रही है, कोई पसंद है या हम रिश्ता ढूंढें? अगर लड़की ने साड़ी पहनी, तो तुरंत कमेंट्री शुरू - वाह, बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही हो। कब ला रही हो दूल्हा घर? और अगर लड़के ने सूट पहना, तो - इतना डैशिंग लुक, अब तो शादी पक्की कर लो। ये लोग कुंवारों को ऐसे घेरते हैं, जैसे सीबीआई किसी मोस्ट-वॉन्टेड को ट्रैक कर रही हो। इनके लिए सिंगल होना कोई लाइफ चॉइस नहीं, बल्कि एक सामाजिक रहस्य है, जिसे ये हर कीमत पर सुलझाने को बेताब रहते हैं।

जैसे ही शादी में खाने की टेबल सजती है, रिश्तेदारों की जीभ तुरंत पांच सितारा फूड क्रिटिक में बदल जाती है। अरे, मलाई कोफ्ते में तो क्रीम का जायका ही गायब है, बस ग्रेवी बनाकर छोड़ दिया। या फिर, ये छोले भटूरे में मसाला कम है, लगता है जल्दबाजी में बनाया है। मिठाई पर इनका फैसला तो किसी शाही फरमान से कम नहीं - ये रसगुल्ले तो डिब्बाबंद हैं, ताजगी का नामोनिशान नहीं। ये लोग थाली को ऐसे खंगालते हैं, जैसे फूड इंस्पेक्टर टेस्टिंग लैब में सैंपल चेक कर रहा हो। और अगर बुफे की लाइन थोड़ी भी लंबी हुई, तो शिकायतों का सिलसिला - इतना इंतजार...? इनके लिए खाना महज भोजन नहीं, बल्कि शादी की इज्जत और रुतबे का चमकदार पैमाना है, जिसे ये हर कौर के साथ नापते हैं, और हर कमी को सालों तक गपशप का तड़कता-भड़कता मसाला बना देते हैं।

भारतीय शादी कोई साधारण आयोजन नहीं, बल्कि एक चमकदार रियलिटी शो है, जहाँ दूल्हा-दुल्हन तो बस मंच सजाने का बहाना हैं, असली तड़का तो रिश्तेदार लगाते हैं। इनके बिना शादी वैसी ही फीकी है, जैसे बिना तड़के की दाल। अपने हाईटेक जीपीएस, तीखी गपशप, और जासूसी स्किल्स के साथ ये लोग हर शादी को एक अनोखा तमाशा बना देते हैं। चाहे वेन्यू की माइक्रोस्कोपिक जांच हो, खाने की थाली का पोस्टमार्टम हो, या गिफ्ट की कीमत का हिसाब-किताब, ये हर मोर्चे पर बाजी मार लेते हैं। इनकी चटपटी टिप्पणियों और ठहाकों के बिना शादी का रंग-रूप अधूरा है। जैसा कि पुरानी कहावत को नया ट्विस्ट देना हो - शादी वो रंगमंच है, जहाँ दो लोग फेरे लेते हैं, और बाकी सब उनकी जिंदगी का लाइव कमेंट्री बॉक्स बनकर तालियाँ और सवाल बटोरते हैं। तो अगली बार शादी में जाएँ, अपने रिश्तेदारों का रडार चालू रखें, और इस धमाकेदार रियलिटी शो का पूरा मज़ा लें।

संकट में जीवन की विविधता: जैव विविधता संरक्षण की पुकार

जैव विविधता केवल पौधों और जानवरों की गिनती भर नहीं है, यह धरती पर जीवन की विविधता और संतुलन की नींव है। आज जबकि जलवायु संकट, वनों की कटाई, और मानवीय दखल प्राकृतिक तंत्र को अस्थिर कर रहे हैं, जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। हालिया शोध यह भी संकेत दे रहे हैं कि जैव विविधता में हस्तक्षेप नए संक्रमणों का कारण बन सकता है। यह समय सजग होने का है।

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

हर वर्ष 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या ये तारीखें और संकल्प धरातल पर असर डाल पा रहे हैं? 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, तब वैज्ञानिकों ने चेताया कि वन्य क्षेत्रों में मानवीय दखल और जैव विविधता से छेड़छाड़ ही ऐसे संक्रमणों के फैलाव का बड़ा कारण है। संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में सतत विकास की दिशा में जो रणनीति बनाई थी, उसमें जैव विविधता के संरक्षण को केंद्र में रखा गया था। इस संकल्प का उद्देश्य था कि दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास के नए अवसर भी तलाशे जाएं। लेकिन, तमाम घोषणाओं और शिखर सम्मेलनों के बावजूद जैव विविधता का संकट और गहराता गया है।

भारत विश्व के उन 17 देशों में है जहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। मात्र 2.4 प्रतिशत भू-भाग वाले भारत में दुनिया की 8 प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें 45,000 से अधिक पादप और लगभग 91,000 जंतु प्रजातियाँ शामिल हैं। भारत की विविध जलवायु, भौगोलिक परिदृश्य, और सांस्कृतिक विविधता ने एक समृद्ध जैव विविधता को पनपने का अवसर दिया है। भारत में 44 प्रतिशत जमीन पर खेती होती है और 23 प्रतिशत भूमि वनाच्छादित है। लेकिन तेजी से हो रहा शहरीकरण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और जीवों के प्राकृतिक आवासों का ह्रास इस संपदा को नष्ट कर रहा है।

भारत में 900 से ज्यादा प्रजातियां संकटग्रस्त हैं और समुद्री पारिस्थितिकी में मौजूद लगभग 1,200 प्रजातियां तत्काल संरक्षण की मांग कर रही हैं। भारतीय वैज्ञानिकों के शोध भी यही कहते हैं - जैव विविधता में असंतुलन, मानव-वन्यजीव संपर्क और भूमि उपयोग में बदलाव - नए संक्रमणों का कारण बन सकते हैं। देश के पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, और इंडो-बर्मी क्षेत्र जैसे क्षेत्र 'हॉटस्पॉट्स' के रूप में चिन्हित किए गए हैं – ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जैव विविधता अत्यधिक तो है, परंतु खतरे में भी है।

भारत सरकार के वन्यजीव संस्थान और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए गए हालिया मूल्यांकन दर्शाते हैं कि भूमि उपयोग में बदलाव, वनों की कटाई, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार जैव विविधता के प्रमुख खतरे बनकर उभरे हैं। वहीं भारतीय समुद्रीक पारिस्थितिक तंत्र भी संकट में है। भारतीय समुद्री जैवविविधता में 20,000 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से लगभग 1,200 प्रजातियाँ अब संकटग्रस्त या अत्यधिक असुरक्षित मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने की गतिविधियों ने समुद्री पारिस्थितिकी पर गंभीर असर डाला है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर द्वारा 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन में स्पष्ट किया गया कि पिछले दो दशकों में भारत के 40 फीसदी से अधिक प्राकृतिक आर्द्रभूमियाँ समाप्त हो गई हैं, जिससे प्रवासी पक्षियों और मछली प्रजातियों का आवास गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है। वहीं सीएसई की 2024 की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास और खनन गतिविधियों ने संरक्षित वन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द जैव विविधता को अत्यधिक क्षतिग्रस्त किया है।

विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट आगाह करती है कि दुनिया के आधे से ज्यादा आर्थिक संसाधन सीधे-सीधे प्रकृति पर निर्भर हैं। वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की करीब 25 प्रतिशत प्रजातियां संकट में हैं। लाखों प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जिनमें से कई इंसानी हस्तक्षेप के कारण अपने मूल आवासों से विस्थापित हो चुकी हैं।

भारत की जैव विविधता केवल पारिस्थितिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, औषधीय और आजीविका के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली, लोकज्ञान और औषधीय परंपराएँ जैव विविधता पर आधारित हैं।

कुछ राज्य सरकारें और जैव विविधता बोर्ड इस दिशा में ठोस पहल कर रहे हैं। केरल जैव विविधता बोर्ड ने 'पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर)' के माध्यम से गाँवों की स्थानीय जैव विविधता का दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी से पौधों, जीवों और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा वैश्विक महत्व का जैव विविधता क्षेत्र माना गया है, लेकिन यहाँ भी हाल के वर्षों में मानवीय हस्तक्षेप और पर्यटक दबाव के कारण वन्यजीवों का व्यवहार प्रभावित हुआ है।

उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड द्वारा 2023 में किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि हिमालयी औषधीय पौधों की लगभग 40 प्रतिशत प्रजातियाँ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अपने प्राकृतिक आवास से खिसक रही हैं। इसके जवाब में राज्य ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सामुदायिक संरक्षण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने जैविक खेती को बढ़ावा देकर रासायनिक खेती से जैव विविधता को होने वाले नुकसान को कम करने में सराहनीय भूमिका निभाई है।

इसके अतिरिक्त, ओडिशा में चिल्का झील के आसपास के पारिस्थितिकीय तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए स्थानीय मछुआरों और ग्राम पंचायतों को शामिल कर जैव विविधता संरक्षण के सफल प्रयास किए गए हैं। महाराष्ट्र के कुछ आदिवासी बहुल जिलों में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन आधारित आजीविका को जैव विविधता के संरक्षण से जोड़ने के नवाचार भी देखने को मिले हैं।

इससे साफ है कि यदि नीति, विज्ञान और समुदाय एक साथ काम करें तो जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। परंतु इसके लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण, स्थायी संसाधन निवेश, और स्थानीय लोगों की भूमिका को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना अनिवार्य है। जैव विविधता केवल जैविक अस्तित्व का प्रश्न नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य और आजीविका का भी आधार है।

वर्ष 2030 तक के वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण अनिवार्य है। हमें अपनी जीवनशैली, नीतियों और विकास के मॉडल को इस दिशा में पुनर्चिंतन करना होगा। जैव विविधता कोई दूरस्थ अवधारणा नहीं, बल्कि धरती पर जीवन के ताने-बाने का मूल आधार है - इसका संरक्षण हमारी साझी ज़िम्मेदारी है।

प्रकृति का मौन क्रंदन, खतरे में जीवन की श्रृंखला

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस

योगेश कुमार गोयल

लेखक पत्रकार हैं।

धरती पर जीवन का आधार केवल मनुष्य नहीं है बल्कि जीव-जंतु, पक्षी, कीट-पतंगे और पेड़-पौधे भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का उतना ही अहम हिस्सा हैं। फिर भी मनुष्य ने अपने स्वार्थों और तथाकथित विकास के नाम पर जिस प्रकार वनों की अंधाधुंध कटाई, वन्य जीवों के आवासों का विनाश और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है, उसने धरती की जैव विविधता को गहरे संकट में डाल दिया है। जैव विविधता केवल कुछ जीवों या पौधों की गिनती भर नहीं है, यह पूरी पारिस्थितिकी का वह संतुलन है, जो जीवन को संभव और सुरक्षित बनाता है लेकिन आज यह संतुलन बुरी तरह से बिगड़ चुका है और इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है। धरती पर अनेक वन्य प्रजातियां या तो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। यही नहीं, हजारों प्रजातियां आज संकटग्रस्त मानी जाती हैं, जिनके अस्तित्व पर हर बीतते वर्ष के साथ खतरा और अधिक बढ़ रहा है। यह संकट केवल जीव-जंतुओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि वनस्पतियों की विविधता भी उसी तीव्र गति से घट रही है।

जैव विविधता के महत्व को रेखांकित करने और लोगों को इसके संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, जिसे 193 देशों ने समर्थन दिया था। 22 मई 1992 को नैरोबी एक्ट के तहत जैव विविधता पर अभिसमय को स्वीकार किया गया था, इसी कारण 22 मई को यह दिवस तय किया गया। इस वर्ष यह दिवस 'प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास' विषय के अंतर्गत मनाया जा रहा है। आज स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि जंगलों के उजड़ने से हजारों पक्षी और जानवर अपने प्राकृतिक आवास से वंचित हो गए हैं। पक्षियों की वे प्रजातियां, जो किसानों के हित में कीट नियंत्रण का काम करती थी, जैसे गिद्ध, कौए, चील, बाज, तीतर, बटेर, मोर आदि, अब संकटग्रस्त हो चुकी हैं। यह केवल जैव विविधता का नुकसान नहीं बल्कि कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरे की घंटी है। ऐसे पक्षी खेतों में कीटों का प्राकृतिक नियंत्रण करते थे लेकिन इनके लुप्त होने से अब कृत्रिम कीटनाशकों की निर्भरता बढ़ रही है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए घातक है।

पर्यावरणीय असंतुलन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग और लगातार बढ़ती आबादी जैव विविधता संकट के प्रमुख कारक हैं। एक ओर जहां जंगलों की अंधाधुंध कटाई के चलते पशु-पक्षियों के प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेड़-पौधों की दुर्लभ प्रजातियां भी मानव गतिविधियों के कारण धीरे-धीरे मिट रही हैं। यही कारण है कि जैव विविधता का संरक्षण आज केवल पर्यावरणविदों का मुद्दा नहीं बल्कि यह पूरी मानव जाति के अस्तित्व से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन गया है। वन्यजीव और वनस्पतियां धरती पर जीवन की लंबी विकास यात्रा की अहम कड़ियां हैं। ये सभी प्रजातियां अरबों वर्षों के जैविक और पारिस्थितिक विकास का परिणाम हैं। वन्य जीवन में वे सभी जीव-जंतु और पौधे शामिल होते हैं, जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला तो नहीं जाता लेकिन उनका अस्तित्व भी मानवीय गतिविधियों से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। जैसे-जैसे जंगल उजड़ते हैं, इन प्रजातियों का जीवन संकटग्रस्त होता जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य ने अपने भौतिक विकास और बढ़ती जनसंख्या के दबाव में इस पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की अनदेखी की है।

यह तथ्य अब वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है कि जैव विविधता के घटने से पर्यावरण का असंतुलन बढ़ता है और इससे प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, अकाल, सूखा, बाढ़, रोगों का प्रसार जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मेरी पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है कि जैव विविधता में आ रही कमी किस प्रकार हमारे संपूर्ण जीवन और पर्यावरण को अस्थिर बना रही है। यह केवल प्रकृति का संकट नहीं बल्कि यह हमारे भविष्य पर मंडराता हुआ खतरा है। धरती पर हर देश की अपनी विशिष्ट जलवायु और पारिस्थितिक पहचान होती है, जिससे वहां की जैव विविधता भी विशिष्ट होती है लेकिन वनों की कटाई, खनन, शहरीकरण, औद्योगीकरण, रासायनिक खेती, प्लास्टिक प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसे मानवीय कारकों ने इस विविधता को संकट में डाल दिया है। दुर्भाग्य से यह संकट केवल कुछ स्थानीय प्रजातियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब यह वैश्विक स्तर पर विनाश की ओर बढ़ रहा है।

आज मानव अपने स्वार्थ और भौतिक जीवन के मोह में यह भूल गया है कि जीवन की आधारशिला प्रकृति ही है। वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पारिस्थितिक तंत्र की अनदेखी मानव को उस दिशा में ले जा रही है, जहां जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। यदि समय रहते हमने चेतना नहीं दिखाई तो आने वाले समय में ऐसी कई प्रजातियां होंगी, जो केवल पुस्तकों और संग्रहालयों में ही मिलेंगी। विकास अनिवार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं परंतु वह विकास, जो प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करके हासिल हो, वह आत्मघाती है। हमें ऐसा विकास मॉडल अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें प्रकृति के साथ सहअस्तित्व को महत्व दिया जाए। यदि पेड़ कटेंगे, जल स्रोत सूखेंगे, जीव-जंतु लुप्त होंगे और पक्षी गायब होंगे तो यह केवल जैव विविधता की हानि नहीं होगी बल्कि पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा।

अब आवश्यकता इस बात की है कि जैव विविधता के संरक्षण को नीतिगत प्राथमिकता दी जाए। सरकारें यदि वन नीति, जल नीति, कृषि नीति और शहरी विकास नीति में पारिस्थितिक संतुलन को अनिवार्य रूप से शामिल करें तो जैव विविधता का संरक्षण संभव हो सकता है। नागरिकों को भी यह समझना होगा कि यह केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर व्यक्ति का दायित्व है। प्रत्येक वृक्ष की रक्षा, जल स्रोतों का संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और जैव विविधता के महत्व को समझना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। जैव विविधता केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि जीवन का मूल आधार है। पृथ्वी की समृद्धि और जीवन की निरंतरता इसी विविधता पर निर्भर करती है। यदि आज हमने संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो कल हमें इसका भयावह मूल्य चुकाना पड़ेगा। जैव विविधता का संरक्षण अब केवल पर्यावरणीय मसला नहीं बल्कि मानव जाति की अस्तित्व रक्षा का संघर्ष बन चुका है।

जो भी दृश्य, अदृश्य, जीवंत हैं, वह सब जैव विविधता का प्रतीक

जैव विविधता दिवस

अमिताभ पाण्डेय

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलनके दौरान जैव विविधता के बारे में बताया गया कि सभी स्रोतों से जीवित जीवन के बीच परिवर्तनशीलता को ही जैव विविधता कहते हैं। इस परिवर्तनशीलता में स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय परिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक परिवर्तन शामिल है। जैव विविधता में प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के बीच, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता आती है। संयुक्त राष्ट्र अन्य देशों में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर जैव विविधता संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहा है। भारत में भी जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए शासकीय स्तर पर, अशासकीय स्तर पर, सामाजिक और समुदाय के स्तर पर विशेष कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहे हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन मंत्रालय सहित अन्य विभाग समन्वय के साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जैव विविधता संरक्षण संबंधी विशेष योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। जैव विविधता का प्रकृति, पर्यावरण, जीव जंतुओं, मनुष्यों सहित अन्य जीवंत इकाइयों से गहरा संबंध है।

हम और हमारे आसपास प्राकृतिक वातावरण में जो कुछ भी दृश्य-अदृश्य-जीवंत है, वह सब जैव विविधता का प्रतीक है। इस पृथ्वी पर प्रकृति में जो रचे-बसे हैं, वे सब जैव विविधता का हिस्सा हैं। जल-जंगल, जीव-जंतु, नदी-पहाड़, समुद्र-दलदल, रेगिस्तान-हरियाली, पेड़ - पौधे, फूल - फल, जड़ी - बूटी - घास, पशु - पक्षी और मनुष्य । जी हां! यह सब कुछ जैव विविधता का हिस्सा है। जैव विविधता के अंतर्गत ही आते हैं। जैव विविधता बहुत व्यापक और जीवंत विषय है। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रजातियों की संख्या, उनकी विविधता, एक ही प्रजाति के अंदर जीन की अनुवांशिकी विविधता, पास्थितिकी तंत्र की विविधता आती है। इसमें वन, घास के मैदान, समुद्री स्थिति की तंत्र भी शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलनके दौरान जैव विविधता के बारे में बताया गया कि 'सभी स्रोतों से जीवित जीवन के बीच परिवर्तनशीलता को ही जैव विविधता कहते हैं। इस परिवर्तनशीलता में स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय परिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक परिवर्तन शामिल है। जैव विविधता में प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के बीच, पारिस्थितिकी तन्त्र की विविधता आती है।'

संयुक्त राष्ट्र अन्य देशों में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर जैव विविधता संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहा है। भारत में भी जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए शासकीय स्तर पर, अशासकीय स्तर पर, सामाजिक और समुदाय के स्तर पर विशेष कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहे हैं । जैव विविधता के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन मंत्रालय सहित अन्य विभाग समन्वय के साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जैव विविधता संरक्षण संबंधी विशेष योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। जैव विविधता का प्रकृति, पर्यावरण, जीव जंतुओं,मनुष्यों सहित अन्य जीवंत इकाइयों से गहरा संबंध है।

जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं प्रदान करती है। जैसे वायु और जल का शुद्धिकरण करना, मिट्टी का निर्माण करना, जलवायु का प्रबंधन करना। जैव विविधता खाद्य सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है क्योंकि यह फसलों, पशुओं को भी प्रजातियों संबंधी विविधता प्रदान करती है। जैव विविधता औषधीय संसाधनों का स्रोत है, जैसे कि पौधे और जानवर जो जिनका प्रकृति में अपना महत्व है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत देश को बहुत समृद्ध माना जाता है भारत के विभिन्न इलाकों में भौगोलिक विविधता और जलवायु की विभिन्नता के कारण जैव विविधता के विविध रूप देखने को मिलते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। इनमें वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल है।

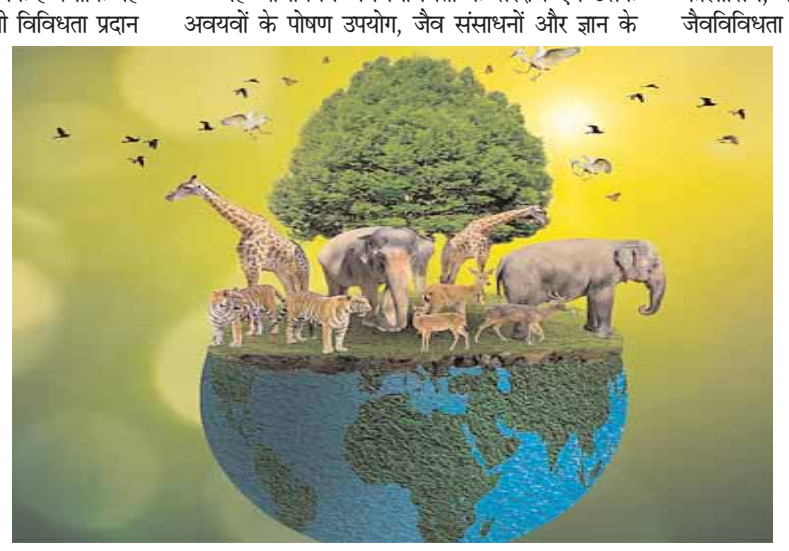

भारत में लगभग 18 हजार विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियां पाई जाती है ।हमारे देश में लगभग 90 हजार विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारे देश में जो वन क्षेत्र,घास के मैदान, दलदल, मरुस्थल, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, नदी, पहाड़, हैं। इन सबका भी जैव विविधता को बनाए रखने में बड़ा महत्व है। भारत में पश्चिमी घाट पर एक विस्तृत पर्वत श्रृंखला है ।इसी प्रकार हिमालय पर्वत की श्रृंखला, सुंदरबन क्षेत्र की मैंग्रोव वन वाली श्रृंखला, जैव विविधता के विशिष्ट उदाहरण है। इसके साथ ही हमारे देश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण है, वह भी जैव विविधता के प्रतीक हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 पारित किया गया है जो कि जैव विविधता के संरक्षण और स्थाई उपयोग के लिए नियमन प्रदान करता है।

यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण एवं उसके अवयवों के पोषण उपयोग, जैव संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से अर्जित लाभ में उचित एवं संपूर्ण हिस्सा बढ़ाने, उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का अपबंधन करने संबंधित है। इस नियम के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जैव विविधता के संदर्भ में प्रकृति ने भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश पर अपना भरपूर प्यार लुटाया है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है । वन एवं वन्य प्राणियों की विविधता है। यहां वन और नदियों की उपस्थिति का बीच संबंध है जिससे जैव विविधता का संरक्षण होता है। वनों की गोद से निकलती सोन, नर्मदा, ताप्ती, चंबल, के साथ ही केन बेतवा, माही, पाहुज, शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, नेवज, जैसी नदियां जनजीवन और जैवविविधता को बेहतर बनाती हैं।

मध्य प्रदेश में विभिन्न पर्वतों की श्रृंखलाएं और उनके जल ग्रहण क्षेत्र जैवविविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। यहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले सागौन मिश्रित साल के वन है। मंडला-डिंडोरी - सिवनी - बालाघाट जैसे जिलों में में साल के वन है तो चंबल क्षेत्र के ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड तथा दतिया में छोटे झाड़ीदार वन हैं। मध्यप्रदेश के बेतूल - हरदा सहित कुछ अन्य जिलों में बहुमूल्य सागौन वृक्ष के वन है। इन वनों से लकड़ी के अलावा बांस और प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की लघु वनोंपज एवं औषधि प्रजातियां मिलती हैं। यह सब जैव विविधता में ही शामिल है।

प्रसंगवश बताते चलें कि मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1860 में हुई और तभी से वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभ हो गया। संभवत- मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां भारत की प्रथम वन नीति अनुसार वर्ष 1994 से ही वर्किंग प्लान बनाने का कार्य किया गया। वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की परंपरा भारत सरकार के वर्तमान उद्देश्यों और नीति निर्देशक के अनुरूप जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन कर रही है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 की धारा 63 (1) के अनुसार मध्य प्रदेश जैव विविधता अधिनियम 2004 दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को अधिसूचित किया गया। इसके अंतर्गत 11 अप्रैल 2005 में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के संगठनों का संवहनीय, पोषणीय उपयोग तथा जीव संसाधनों के ज्ञान के वाणिज्यिक उपयोग से अर्जित लाभ का उचित और साम्य पूर्वक वितरण करना है।

मध्य प्रदेश में जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर शोध, दस्तावेजीकरण परियोजनाएं, महाविद्यालयों एवं अशासकीय संस्थाओं के सहयोग से संचालित की जा रही है। वर्ष 2024-25 में कुल 24 परियोजनाएं संचालित की गई जिनके माध्यम से जैव विविधता के बारे में जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। जैव विविधता के संरक्षण एवं संरक्षण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य सहयोगी विभागों के माध्यम से प्रतिवर्ष विद्यालय छात्र-छात्राओं के लिए मोगली बाल उत्सव का आयोजन किया जाता है।

मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय मोगली उत्सव वर्ष 2024 का आयोजन पेंच टाइगर रिजर्व जिला सिवनी में दिनांक 11 से 13 नवंबर 2024 तक किया गया। प्रदेश के सभी 52 जिलों के चयनित 242 विद्यार्थियों एवं 108 शिक्षकों ने मोगली बाल उत्सव में भाग लिया ।मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा नेचर ट्रेल, ट्रेजर हंट, हैबिटेट सर्च, स्पार्क सफारी, जैव विविधता प्रदर्शनी, चलित जैव विविधता विज्ञान प्रदर्शनी संबंधी अनेक कार्यक्रम संचालित किया जा रहे हैं। इनके माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन हेतु जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

कांग्रेस नेताओं ने मूंग खरीदी को लेकर ज्ञापन सौंपा

सुबह सवेरे, सोहागपुर। कांग्रेस नेता पुष्पराज सिंह पटेल के नेतृत्व में तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।इस ज्ञापन में नर्मदापुरम जिले में मूंग खरीदी करने एवं गेहूं के फसल का भुगतान शीघ्र करने का आग्रह किया गया है। किसानों की तकलीफ़ पर ध्यानाकर्षण करते हुए कहा है कि किसानों की मूंग की फसल

पककर तैयार है ।लेकिन अभी तक शासन ने मूंग की शासकीय समर्थन मूल्य की खरीदी कब की जाएगी, कैसी की जाएगी ,और कब की जाएगी। इस संबंध में शासन के द्वारा कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। नहीं किसानों के मूंग का रजिस्ट्रेशन कार्य शुरू हुआ है। जिससे किसानों में भय एवं गुस्सा व्याप्त है । व अतः शासन से निवेदन है कि मूंग की खरीदी के लिए आवश्यक कदम उठाये जाए। वहीं ज्ञापन में कहा गया है कि अभी तक जिले के किसानों का गेहूं की फसल पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है। इससे किसान चिंतित हैं। हमारा निवेदन है कि किसानों की फसल का अतिशीघ्र का शेष भुगतान कराया जाए। अगर हमारी मांगो पर विचार नहीं किया गया तो किसानों का बड़ा आंदोलन सोहागपुर में करने को मजबूर होना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पुष्पराज सिंह पटेल, मनीष पटेल,प्रदम्म पटेल,अम्मान खान,नगर कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौधरी,नीरज चौधरी, इरफान खान सहित कई किसान उपस्थित थे।

राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की

सोहागपुर। पलकमती नदी के समीप मालवीय कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। उपस्थित कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पुष्पराज सिंह पटेल ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश को नई दिशा प्रदान की थीं। वहीं कई वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पुष्पराज सिंह पटेल, प्रकाश मालवीय,नीरज चौधरी,नगर कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौधरी, इरफान खान, नीरज रघुवंशी, वकील कार्तिक शर्मा आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के सारणी आगमन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक

बैतूल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 28 मई को सारणी आगमन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। बुधवार को कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार हेलीपैड और टेंट निर्माण कराने के निर्देश दिए। साथ ही, एमपीईबी को कार्यक्रम स्थल पर विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। कार्यक्रम स्थल पर विभागीय प्रदर्शनी लगाने के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को निर्देशित किया गया है। वहीं, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को वाहनों की उपयुक्त व्यवस्था करने को कहा गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को कार्यक्रम स्थल पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जबकि नगरपालिका को स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही, नगरपालिका सारणी को पार्किंग की समुचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्बाध आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सारणी मार्ग पर यातायात सुचारू बनाए रखने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए गए हैं। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी, संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिवक्ता संघ बैतूल की चुनाव तिथि घोषित

मुख्य चुनाव अधिकारी मिश्रा नियुक्त

बैतूल। जिला अधिवक्ता संघ बैतूल के वर्ष 2025 के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी 7 सदस्यों के पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। जिसकी घोषणा मुख्य चुनाव अधिकारी अधिवक्ता नितिन मिश्रा बैतूल एवं सहायक चुनाव अधिकारी अधिवक्ता राकेश पटेल बैतूल द्वारा 21 मई को जारी की गई है। प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। जिस पर दावे आपत्तियां 21 मई से 24 मई समय 4 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 मई को होगा। नामांकन फार्म वितरण दिनांक 28 मई से 3 जून तक प्रदाय कर जमा किए जायेंगे नामांकन फार्म की जांच व प्रत्याशी की सूची का प्रकाशन होगा। 5 जून एवं 6 जून को शाम 4 बजे तक नामांकन फार्म वापसी अभ्यार्थी कर सकेंगे। अंतिम प्रत्याशी की सूची का प्रकाशन 6 जून को शाम 5 बजे होगा। मतदान 27 जून को समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। मतगणना 27 जून को अंतिम घोषणा तक शाम 7 बजे से होगा।

ई-ऑफिस प्रशिक्षण का सफल आयोजन, 271 शासकीय सेवकों ने प्राप्त किया प्रशिक्षण

बैतूल। जिले के विभिन्न विभागों के शासकीय सेवकों हेतु ई-ऑफिस प्रणाली के उपयोग में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण 13 मई से 21 मई 2025 तक ई-दक्ष केंद्र, बैतूल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 271 शासकीय सेवकों ने भाग लिया, जिन्हें 14 बैचों में विभाजित कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रतिभागियों को ई-ऑफिस के संचालन, दस्तावेज प्रबंधन, फाइल ट्रैकिंग तथा अन्य डिजिटल प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।

नालों की सफाई में बाधा बन रहा अतिक्रमण, बारिश में जलभराव होने से होगी परेशानी

नहीं उतर रही मशीन, जेसीबी से बनाना पड़ रहा रास्ता

बैतूल। बारिश में शहर के निचले स्थानों पर जलभराव की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए नगरपालिका शहर के नालों की सफाई करवा रही है, ताकि बारिश का पानी बिना रूकावट के निकल सके, लेकिन सफाई के इस काम में अतिक्रमण बाधा बन रहा है। दरअसल सफाई के लिए नाले में पोकलेन मशीन उतारना नगर पालिका अमले के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रह है। अतिक्रमण की वजह से नाले में जाने के सभी रास्ते बंद हैं। ऐसे में कई हिस्सों में नाला सफाई का काम अधूरा है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में सफाई शुरू नहीं हो पाई है। यदि बारिश से पहले नाला सफाई नहीं होती है तो बाढ़ की स्थिति में निचली बस्तियों में पानी भरने की संभावना बनी रहेगी। खासकर शहर के इंदिरा नगर, विनोबा वार्ड, संजय कॉलोनी, भगत सिंह वार्ड, रामनगर क्षेत्र, ढीमर मोहल्ला, जयप्रकाश वार्ड सहित अन्य क्षेत्रों में हर साल नाले की वजह से जलभराव की स्थिति बनती है। पिछले साल तेज बारिश की वजह से कई घरों में बारिश का पानी घुस गया था। ठीक से नाला सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो सकी थी। इस बार भी जिस तरह से नाला सफाई काम चल रहा है, उसे देखते हुए लगता नहीं कि नालों में ऊफान आने

पर पानी की निकासी ठीक तरह से हो पाएगी, क्योंकि घनी आबादी क्षेत्रों अंदर की तरफ नालों की स्थिति जस की तस है।

शहर में है प्रमुख 4 नाले- शहर के बीच से हाथी नाला सहित 4 बड़े नाले गुजरते हैं। इनमें बाढ़ व जलभराव जैसी स्थिति से बचाव के लिए बारिश से पहले सफाई की जरूरत पड़ती है। हर साल सफाई के बाद भी नालों का हाल यह है कि कई हिस्सों में झाडियां, गंदगी और गाद जमा है। इसके लिए चैन माउंटिंग मशीन और मैनुअल दोनों तरीकों से सफाई का सहारा लेना पड़ता है। नालों की सफाई में नगरपालिका को हर साल करीब 15 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी नालों की हालत खस्ताहाल है। विनोबा वार्ड में संजय कॉलोनी के पीछे बहने वाले नाले की सफाई के लिए नाले के पास बनी पुलिया के साइट से जेसीबी मशीन से रास्ता तैयार करवाया गया और उसके बाद पोकलेन मशीन को नाले में उतारा गया।

अतिक्रमण से घिरे शहर में अंदर बहने वाले नाले- शहर के अंदर बहने वाले अधिकांश नाले अतिक्रमण से घिरे हुए हैं। लोगों ने नालों के किनारों तक पर अतिक्रमण कर लिया है। जिसकी वजह से नाले तक मशीन को लेकर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। बताया गया कि शहर का सबसे बड़ा नाला हाथी नाला हैं, लेकिन यह भी अतिक्रमण से घिरा हुआ है। जिसके कारण नाले की सफाई करना मुश्किल होता है। कुछ जगहों पर रास्ते बनाकर नाले की सफाई कराई गई है, लेकिन अधिकांश भाग में नाला गंदगी से पटा हुआ है। ऐसे में नाला सफाई ठीक से नहीं होने पर बारिश के दौरान निचली बस्तियों में जल भराव की संभावना बनी हुई है। बारिश के पहले सभी नालों की सफाई पूरी होना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि शहर में एक नाला नहीं है, बल्कि चार से पांच नाले अलग-अलग दिशाओं में बहते हैं। ऐसे में सभी जगहों पर मशीन ले जाकर तय समय में सफाई करना मुश्किल नजर आ रहा है।

2300 रूपये प्रति घंटे हो रही नाले की सफाई

गंदगी और प्रदूषण से मुक्ति के नाम पर शहर में नालों की सफाई में हर साल लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नालों के आसपास अतिक्रमण होने की वजह से मशीन सफाई के लिए नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में नाला सफाई होने के बाद भी हालत जस के तस हो जाते हैं। नगरपालिका ने नाला सफाई के लिए बारिश के पहले ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। जानकारी के अनुसार इस बार 2300 रुपए प्रति घंटे की दर से नाला सफाई का काम कराया जा रहा है। पिछले साल 2100 रुपए प्रति घंटे की दर से नालों की सफाई हुई थी। नगरपालिका ने मई से नाला सफाई का काम शुरू भी करा दिया है। इंदिरा कॉलोनी मुले नर्सिंग होम के पीछे से नाला सफाई मशीनों के माध्यम से की जा रही है। बताया गया कि बारिश के पहले तक नाला सफाई का काम चलेगा।

इनका कहना है

नालों की सफाई का काम जारी है। बारिश के पूर्व सभी नालों की सफाई कार्य पूरा कर लिया जायेगा। यदि मशीन उतारने के लिए सही जगह मिले तो सभी नालों की सफाई बारिश के पहले हो सकती है। हालांकि जहां-जहां अतिक्रमण है वहाँ से जल्द अतिक्रमण भी हटाएंगे।

- संतोष धनेलिया स्वच्छता निरीक्षक नगर पालिका बैतूल

नपा आमला ने कराया आधा दर्जन नए नलकूप खनन, पेयजल की समस्या से मिलेगी राहत

लालवाड़ी जलाशय के पूरी तरह सूखने से हुआ जलसंकट

आमला। लगभग 30 करोड़ की लागत से बने लालावाड़ी स्थित जलाशय के पूरी तरह सूख जाने से शहर में जल संकट के हालात बन गए थे और शहर के कई इलाकों में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह ठप्प पड़ गई थी। जिसको लेकर लोग नगर पालिका के दफ्तर पहुंचकर अपना गुस्सा भी जता रहे थे, इसे देखते हुए नगर पालिका के प्रयासों से शहर और आसपास के कुछ इलाकों में फिलहाल नए नलकूप कराए गए हैं जिन्हें चालू भी कर दिया गया है, इसे फिलहाल शहर में बने जल संकट के हालातों से निपटने में नगर पालिका को कुछ हद तक सहायता मिली है।

नगर पालिका की जलशाखा के अधिकारी ने बताया कि शहर से सटे आवरिया मोक्षधाम वार्ड क्रमांक 12 आदि इलाकों में सात नए नलकूप कराए गए हैं। उन्होंने बताया है की आवश्यकता अनुसार कुछ और भी नए नलकूप कराए जा सकते हैं। नगर पालिका को भरोसा है कि इस नई व्यवस्था से जहां फिलहाल एक बड़ी राहत शहर को मिली है, तो वहीं आगामी समय में भी यह नए जल स्रोत पेयजल की समस्या से निपटने में कारगर साबित हो सकते हैं। गौरतलब है कि बीते लगभग एक माह से शहर के सभी वार्डों में दो दिन के अंतराल से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, तो वहीं पानी के टैंकरों से भी इलाकों में आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जा रही है।

इनका कहना है

अभी सात नए नलकूप कराए गए हैं, जिससे शहर में पेयजल की समस्या से निपटने में कुछ हद तक राहत मिली है और यही नलकूप आने वाले समय में भी पेयजल संकट के दौरान नगर पालिका की बड़ी मदद करेंगे।

- वीरेंद्र तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, आमला

टीबी मुक्त पंचायत अभियान में बैतूल जिले को उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला राज्य स्तरीय सम्मान

बैतूल। टीबी मुक्त पंचायत अभियान के अंतर्गत बैतूल जिले को उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। राजधानी भोपाल स्थित सांदीपनि सभागार, राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा बैतूल जिले को यह सम्मान प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग ने बैतूल जिले की 219 ग्राम पंचायतों में इस अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्य कर क्षेत्र को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जिले को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान से नवाज़ा गया। सम्मान समारोह के अवसर पर बैतूल जिले की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी अक्षत जैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश परिहार, जिला क्षय अधिकारी डॉ. आनंद मालवीय, तथा जिला समन्वयक अजय नागले ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस सम्मान से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता और समर्पण को नई ऊर्जा मिली है। जिले की इस सफलता से अन्य जिलों को भी प्रेरणा प्राप्त होगी।

शाहपुर के जंगल में मिला नर भालू का सड़ा-गला शव

करंट से मौत की आशंका, वन विभाग की टीम जांच में जुटी

बैतूल। शाहपुर वन क्षेत्र के पूर्व बांका कांटावाडी इलाके में एक नर भालू का सात दिन पुराना शव मिला है। शव की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इको सेंटर भेजा गया। वन विभाग के अनुसार मृत भालू वयस्क था और उम्र करीब 15 साल बताई जा रही है। शव की स्थिति देखकर अनुमान लगाया गया कि उसकी मौत करीब एक हफ्ते पहले हुई होगी। शुरुआती जांच में करंट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। डीएफओ नवीन गर्ग ने कहा कि यह पता लगाया जा रहा है कि भालू की मौत स्वाभाविक थी या फिर किसी तरह की मानव गतिविधि इसकी वजह बनी। टीम जांच में जुटी है। सूत्रों के अनुसार, इस इलाके में जंगली खरगोश और अन्य छोटे वन्य प्राणियों के शिकार के लिए करंट और फंदों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। आशंका है कि भालू भी इसी कारण शिकार हो गया हो। जांच के दौरान वन अधिकारियों ने कुछ बांस और लकड़ी की खपच्चियां भी बरामद की हैं, लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।

पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ अंतरराज्यीय अफीम तस्करी का आरोपी

पुलिस ने नाकाबंदी कर सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की जांच की शुरू

बैतूल। अफीम तस्करी के आरोप में पकड़ा गया गोपाल बंजारा जिला अस्पताल से फरार हो गया। राजस्थान पुलिस उसे मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर आई थी। इसके बाद उसे वापस जेल भेजना था, लेकिन इससे पहले वह भाग गया। पुलिस फरार आरोपी को ढूंढने में लगी है। इस मामले में राजस्थान पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। राजस्थान पुलिस ने स्थानीय पुलिस कर्मियों की मदद नहीं ली। अंजाम यह सामने आया कि आरोपी पुलिस के हाथ से फरार हो गया। कोतवाली थाना प्रभारी रविकांत डेहरिया ने बताया कि कुछ दिन पहले नीमच निवासी गोपाल बंजारे को अफीम की खेती के मामले में बैतूल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी पर राजस्थान में भी अफीम की खेती करने का मामला दर्ज था। बैतूल पुलिस ने आरोपी को राजस्थान पुलिस को सौंपा था। पुलिस आरोपी को राजस्थान से बैतूल लेकर आई बैतूल पुलिस को आरोपी को सौंपने के पहले मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल बैतूल लाया गया। आरोपी

को ईसीजी के लिए कक्ष में हथकडी निकालकर भेजा, ईसीजी करते समय आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर भाग गया। अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में गोपाल बंजारा को सड़क पर दौड़ते हुए देखा गया है। जिला पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी करते हुए सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में बैतूल एसपी निश्चल एन. झारिया ने बताया कि आरोपी की तलाश में जिलेभर में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही, जिन पुलिसकर्मियों की कस्टडी से आरोपी भागा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई शिव महापुराण कथा

पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर किया गया रुद्राभिषेक

बैतूल। शहर के हाऊसिंग बोर्ड कालोनी में बुधवार 21 मई से 21 हजार रुद्री निर्माण एवं भव्य रुद्राभिषेक एवं श्री शिवमहापुराण प्रवचन सप्ताह की शुरूआत हुई। इस धार्मिक अनुष्ठान के शुभारंभ अवसर पर भव्य विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जो आयोजन स्थल से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस आयोजन स्थल पहुंची।

यात्रा में दिव्य झांकियों ने अपनी सुंदर प्रस्तुति दी। बुधवार से प्रतिदिन सुबह रुद्री निर्माण प्रातः 08 बजे से एवं रुद्राभिषेक प्रातः 10 बजे वाराणसी से पधारे विद्वानों द्वारा अभिषेक प्रारंभ किया गया।

कथा व्यास पंडित रोहित दुबे नर्मदापुर ने शिवपुराण ही महिमा श्रवण कराई एवं पूज्य स्वामी चंद्रशेखरानंद महाराज (श्रीविद्या आश्रम शिवपुर) 22 मई से 24 मई 2025 तक 04 बजे से 07 बजे तक प्रवचन होंगे एवं पूज्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियानन्द जी महाराज (अंडिया घाट रायसेन) 25 मई से 27 मई 2025 तक 04 बजे से 07 बजे तक कथा का वाचन किया जायेगा। संयोजक पंडित अनुराग मिश्रा ने शहर के सभी श्रद्धालुओं से धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने का आग्रह किया है। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर कार्यक्रम में तन, मन, धन से सहयोग करें

जल गंगा संवर्धन अभियान का सफल आयोजन

बैतूल। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा विकासखंड शाहपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान का सफल आयोजन किया गया। यह अभियान ग्राम पंचायत मूढ़ा के अंतर्गत ग्राम कोठा में चलाया गया, जहां स्थित एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक जल स्रोत झिरिया फाटक नाला की सफाई कर उसे पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य किया गया। इस जनभागीदारी वाले अभियान में समाज कार्य के स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों,

परामर्शदाताओं तथा नवांकुर संस्थाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान का मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों की सफाई के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देना एवं जन जागरूकता फैलाना था। सफाई कार्य के पूर्ण होने के पश्चात एक जल संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जल संरक्षण और संवर्धन के महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई। संगोष्ठी के दौरान उपस्थित सभी स्वयंसेवकों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई, जिससे भावी पीढ़ी में जल के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। इस अवसर पर ग्राम पंचायत मूढ़ा के पूर्व उपसरपंच, सुमन जन जागृति संस्था कोठा, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति सिलपटी, जय गुरुदेव उत्थान संस्था, सीएमसीएलडीपी के विद्यार्थी की उपस्थिति रही।

देवी अहिल्याबाई होल्कर की तरह महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे मोदी : विनीता धर्म

भाजपा ने लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर जिला स्तरीय विचार गोष्ठी आयोजित

धार। लोकमाता पुण्यश्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर जिला स्तरीय विचार गोष्ठी भाजपा जिला कार्यालय में बुधवार को आयोजित की गई। जिला स्तरीय विचार गोष्ठी में में मुख्य वक्ता प्रदेश स्तरीय समिति सदस्य विनीता धर्म के रूप में उपस्थिति रही । गोष्ठी की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती कार्यक्रम संयोजक देवेंद्र सोनाने सह संयोजक कुसुम सोलंकी जिला टोली सदस्य , रोमा मंडलोई, मोहित तातेड बदनावर नगर परिषद अध्यक्ष मीना यादव मंचासीन रहे ।

स्वागत उद्बोधन में भाजपा जिला अध्यक्ष निलेश भारती ने कहा कि अहिल्याबाई- होल्कर ने अपने समय मे जो धार्मिक,सामाजिक और संस्कृतिक उत्थान के कार्य किए थे,उसी की प्रेरणा स्वरूप केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी देशभर में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के कार्य कर रही है। इस अभियान में समावेशी एवं सुशासन को लेकर भाजपा के विजन और रानी अहिल्याबाई की विरासत को जोड़कर पेश किया जाएगा। इस दौरान महिला सशक्तिकरण एवं लोक कल्याण से जुड़ी केंद्र व भाजपा शासित राज्यों की योजनाओं का भी प्रचार किया जाएगा। मुख्य वक्ता विनीता धर्म दीदी ने कहा कि जिस तरह से 300 वर्ष पहले देवी अहिल्याबाई ने महेश्वरी साड़ियों के माध्यम से बहनों के सशक्तीकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए थे, वैसे ही कार्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उन्होंने लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन को समझते है तो हम बहुत कुछ सीख सकते है उन्होंने देश में 35 सौ से अधिक मंदिर बनाए एवं मंदिरों का जीणोद्धार किया।वह न्याय मूर्ति और किसानों के प्रति दूर दृष्टि थी। कार्यक्रम जिला संयोजक देवेंद्र सोनाने ने कहा कि मालवा की शासक रही देवी अहिल्याबाई होल्कर की 320 वी जयंती पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में 21 में से 31 तक समावेशी सुशासन अभियान चलाएगी इस अभियान में अहिल्याबाई होल्कर की विरासत के प्रचार के साथ भाजपा के समावेशी को सुशासन मॉडल का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा इस अभियान के तहत प्रदर्शनी,महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन, सिंदूर यात्रा, रंगोली, भाषण प्रतियोगिता, मैराथन दोड, कवि सम्मेलन, बालिकाओं का सम्मान, नृत्य नाटिका, नुक्कड़ नाटक,संगोष्ठी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ममता जोशी सुषमा पाठक अनामिका ठाकुर गायत्री पुरोहित निशा शर्मा डाली जाधव सहित महिला मोर्चा पदाधिकारी व बड़ी संख्या में मातृ शक्ति उपस्थित रही। संचालन अल्पना जोशी ने किया। जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने दी।

संक्षिप्त समाचार

खाद्य तेल के नमूने लिए गए

विदिशा (निप्र)। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती एडलिन ई पन्ना ने आज विदिशा नगर में गुरुद्वारे के पास स्थित मुस्कान ट्रेडर्स (रिपेकर) का औचक निरीक्षण कर खाद्य तेल सोयाबीन तेल लूज एवं सोयाबीन तेल ब्रांड मुस्कान के नमूने जांच हेतु लिए हैं। खाद्य कारोबारकर्ता को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य तेल खुला विक्रय करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्यवाही जिले में लगातार जारी है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप वर्मा द्वारा तहसील त्योंदा स्थित जैन किराना से नमकीन एवं दूध पाउडर के नमूने लिए गए हैं। श्रीमती किरण एम श्रीवास्तव ने तहसील ग्यारसपुर स्थित अनिल किराना से नमकीन तथा वनस्पति के नमूने एकत्रित किए। उक्त कार्यवाहियों में लिए गए नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

270 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया

विदिशा (निप्र)। वन मंडलाधिकारी श्री हेमंत यादव के मार्गदर्शन सह निर्देशन में आज 270 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया कराया गया है। परिक्षेत्र शमशाबाद अंतर्गत कक्ष क्रमांक 248 एवं 248 बीट कोलुआ में 270 हेक्टेयर वन भूमि को वनमण्डलाधिकारी के निर्देशन में अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, उक्त भूमि पर कई वर्षों से खेती हो रही थी। वन राजस्व एवं पुलिस के संयुक्त बल द्वारा कार्यवाही कर 270 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उक्त भूमि पर कई वर्षों से ग्राम मानाखेड़ी एवं झगरी के ग्रामीणों द्वारा खेती की जा रही थी। अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही जारी है। अतिक्रमण मुक्त कराई गई वन भूमि पर सीपीटी खोदी गई एवं रोपण हेतु जमीन को आरक्षित किया गया।

विद्युत वितरण कम्पनी के ऑपरेटर के साथ मारपीट करने पर एफ आई आर दर्ज

हरदा (निप्र)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा हरदा वृत्त के पोखरनी वितरण केन्द्र अंतर्गत शासकीय कार्य मैं बाधा डालने एवं ऑपरेटर से मारपीट करने वाले आरोपित के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है। सहायक प्रबंधक टिमरनी मोनिका सिंह ठाकुर ने बताया कि उपकेन्द्र पोखरनी के ऑपरेटर प्रकाश ग्वहारिया पिता मोहन लाल ग्वाहरिया के साथ ग्रामीण कुलदीप रायखेरे ने गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। इसके खिलाफ थाना टिमरनी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उल्लेखनीय है कि आरोपित श्री कुलदीप रायखेरे ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पोखरनी वितरण केन्द्र सब स्टेशन में आपरेटर के पद पर पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारी श्री प्रकाश गुहारिया से जबरदस्ती सब स्टेशन के गेट का ताला खुलवाकर मारपीट की तथा विद्युत उपकरणों को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। रात में बिजली चले जाने की बात कहते हुए आरोपित द्वारा मारपीट की गई और कंट्रोल पैनल में लात मारकर रिले तोड़ दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र की लाइट चली गई।

खनिज के अवैध परिवहन में शामिल 4 डम्पर जप्त किये

हरदा (निप्र) कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देशन मे जिले मे खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के रोकथाम की कार्यवाही लगातार जारी है। जिला खनिज अधिकारी श्री आर.पी. कमलेश ने बताया कि रविवार को खनिज विभाग के दल ने खनिज के अवैध परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही कर 4 डम्पर जप्त किये। कार्यवाही के दौरान जो वाहन जप्त किये गये उनमें वाहन मालिक रितेश शर्मा, मौसम रेस्टोरेंट हरदा के अस्पष्ट नंबर का डंपर, वाहन मालिक मयंक जैन, निवासी हरदा के डम्पर क्रमांक एमपी 47 एच 0280 तथा वाहन मालिक श्री जी इन्फ्रा.कंस्ट्रक्शन कंपनी ग्राम - बरबई तहसील खातेगांव के डम्पर क्रमांक आरजे 14 जीएच 9141 व आरजे 14 जीएच 9153 शामिल है।

राम राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है मर्यादा व धैर्य: पं. श्याम स्वरूप मनावत

स्व. दत्ताजी उननगांवकर स्मृति सेवा न्यास धार द्वारा आयोजित 'राजा भोज स्मृति व्याख्यानमाला' के पहले दिन व्यक्त विचार

धार। दत्ताजी उननगांवकर स्मृति सेवा न्यास धार द्वारा आयोजित 'राजा भोज स्मृति व्याख्यानमाला' के पहले दिन प्रसिद्ध भागवत आचार्य और कथावाचक पंडित श्याम स्वरूप मनावत ने %राम राज्य की अवधारणा और स्वरूप% विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राम राज्य की स्थापना केवल सत्ता से नहीं, बल्कि मर्यादा, त्याग और संतों की इच्छाओं के अनुरूप जीवन जीने से संभव है।

इस धरती पर राम राज्य लाने के प्रयास सर्वप्रथम महाराज दशरथ ने किए थे। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक और गोखले जैसे महापुरुषों ने भी देश में राम राज्य स्थापित करने का सपना देखा। कलयुग में राम राज्य लाने के लिए धैर्य और त्याग की आवश्यकता है।

यह विचार पंडित श्याम स्वरूप मनावत ने बुधवार को स्व. दत्ताजी उननगांवकर स्मृति सेवा न्यास धार द्वारा आयोजित 'राजा भोज स्मृति व्याख्यानमाला' के पहले दिन व्यक्त किए। इस दो दिवसीय आयोजन में उन्होंने 'राम राज्य की अवधारणा और स्वरूप' विषय पर लगभग एक घंटे तक अपने विचार साझा किए। पं. मनावत ने कहा कि जिस प्रकार राजा दशरथ ने सत्ता का मोह त्यागकर भविष्य की पीढ़ी के लिए आदर्श स्थापित किया, उसी प्रकार आज भी त्याग और मर्यादा का अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि दशरथ ने राम को केवल इसलिए राजा नहीं बनाया कि वे उनके पुत्र थे, बल्कि इसलिए क्योंकि भगवान राम ने कभी खुद की प्रशंसा नहीं की, वे कभी स्वजन की प्रशंसा के इच्छुक नहीं रहे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे जिन्होंने अपने शत्रुओं से प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राम राज्य की स्थापना के चार आधार हैं–त्याग, सेवा, मर्यादा और न्याय। आज भी ये चारों आधार उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि शासन की इच्छा से नहीं, संतों की इच्छा से ही राम राज्य की प्राप्ति संभव है।

पं. मनावत ने 'मंथरा (कुप्रवृत्ति) को राम राज्य में सबसे बड़ी बाधा बताया। उन्होंने कहा कि मंथरा जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां आज भी समाज में मौजूद हैं। आजकल तो पढ़ी-लिखी 'मंथराएं' भी हैं, जो हर क्षेत्र में विघ्न डाल रही हैं। इनसे सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले 500 वर्षों में कई ऐसी मंथराओं ने भगवान राम को उनके ही मंदिर में स्थापित होने से रोके रखा। अब समय आ गया है कि हम ऐसी प्रवृत्तियों की पहचान करें और उनका उचित उपचार करें।

पक्षीराज जटायु का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जटायु भले ही रावण को नहीं रोक पाए, पर उन्होंने संघर्ष करके दिखाया कि जिंदगी को सार्थक कैसे बनाया जाता है। उन्होंने वर्तमान समाज में केवल सफल और कुशल व्यक्तियों के सम्मान की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाया और कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, उनका सम्मान भी उतना ही जरूरी है।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद जैसी सामाजिक बुराइयों का कारण उदासीनता, जातिवाद और लापरवाही है। यदि हम इनसे ऊपर उठें, तभी हम राम राज्य की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें इंद्रजीत नहीं बनना है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला बनना है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्व. दत्ताजी उननगांवकर स्मृति सेवा न्यास धार के अध्यक्ष ललित जी कोठारी थे। व्याख्यान माला आयोजन समिति, धार के अध्यक्ष डा. दिनेश कर्मा ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की। अतिथि परिचय राखी राय ने दिया। एकल गीत राजेश रघुवंशी ने प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत बाबूलाल चौधरी, प्रवीण गोधा, वैभव निगम ने किया। मुख्य अतिथि को प्रतीक चिन्ह विष्णु शास्त्री व परिणय अग्रवाल ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन अभय किरकिरे ने किया। आभार प्रदर्शन समिति के सचिव एडवोकेट सिद्धार्थ जैन ने किया। अंत में राष्ट्रगान पं गोपाल जोशी ने प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुलताई में खाद्य पदार्थों के लिए सैम्पल

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की सघन जांच एवं नमूने लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन श्री शैलेंद्र बड़ोनिया के मार्गदर्शन में खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जा रही है।

इसी क्रम में सोमवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती शशि भारतीय द्वारा मुलताई के सावजी रेस्टोरेंट से सोयाबीन तेल , आटा, व धनिया पाउडर के,आकाश चाय से दो चायपत्ती के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती मीना कुमारे द्वारा तिलक जनरल स्टोर आठनेर से टोमेटो केचप, साबूदाना व शरबत के नमूने लिए गए। लिए गए सैंपल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। यह कारवाई सतत जारी रहेगी।

कलेक्टर श्री जैन ने हृदय अभियान की समीक्षा की

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में हृदय अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होने निर्देश दिये कि गर्भवती महिलाओं का शतप्रतिशत पंजीयन किया जाए तथा स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाएं और प्रयास किया जाए कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से छूटे नहीं। उन्होने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभागीय अमले के माध्यम से एक बार फिर से गांव-गांव में विस्तृत सर्वे करें तथा ऐसे ग्रामीणों को चिन्हित करें, जो अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य व महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं ले पा रहें हैं। कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि ऐसे परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण व टीकाकरण जैसी सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं।

हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित संस्थागत प्रसव की व्यवस्था करें

कलेक्टर श्री जैन ने बैठक में निर्देश दिये कि स्वास्थ विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं का गर्भावस्था के दौरान कम से कम तीन बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। हाई रिस्क वाली महिलाओं को पहले से ही चिन्हित कर उनके सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था पहले से कर ली जाए। उन्होने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि गर्भवती महिलाओं में जिनकी समग्र आईडी नहीं है, उनकी आईडी बनवाएं तथा जिन महिलाओं के खाते बैंकों में नहीं खुले है, उनके खाते खुलवाए जाएं ताकि शासन की योजनाओं के तहत इन महिलाओं को दी जाने वाली राशि इनके खातों में जमा की जा सके। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी.एस. रघुवंशी, डी.पी.सी श्री बलवन्त पटेल के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका मिशन, वन विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

पात्र हितग्राही का आवेदन अस्वीकृत होने पर सम्बंधित अधिकारी-कर्मचारी से होगी हितलाभ की राशि वसूल : कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी

बैतूल (निप्र)। शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र वंचित न रहे। अगर लापरवाही के चलते किसी पात्र हितग्राही का आवेदन अस्वीकृत होता है तो, वंचित अवधि की हितलाभ राशि संबंधित अधिकारी, कर्मचारी से वसूल की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में सभी अधिकारी, कर्मचारियों को दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए की वे अपने दायित्वों का पूरी गंभीरता और तत्परता से निर्वहन करें। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बैठक में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने उपसंचालक सामाजिक न्याय को निर्देशित किया कि सचिव स्तर से लापरवाही के कारण किसी पात्र व्यक्ति का आवेदन अस्वीकृत किया गया है, तो संबंधित सचिव के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें और हितलाभ राशि भी वसूल की जाए। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जल गंगा संवर्धन अभियान की भी विभागवार प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व विभाग को दर्ज होने से शेष नहरों को भी राजस्व अभिलेख में शीघ्र दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग को माइल्स स्टोन लगाने की कार्यवाही भी शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। सभी नगरी निकायों को हरित क्षेत्र विकास, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि विभिन्न विभागों से समन्वय कर रिचार्ज शॉप निर्माण कार्य को पूरा कराएं। सभी जनपद सीईओ और तहसीलदार को अमृतसर ओवर के कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने राशन हितग्राहियों के ईकेवाईसी कार्य में अच्छी प्रगति पर फूड विभाग की प्रशंसा की और शेष लक्ष्य को भी 31 मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने सभी जनपद सीईओ और सीएमओ को भी निर्देशित किया कि समग्र से आधार लिंकिंग की कार्यवाही भी पूरी गंभीरता से पूर्ण कराएं। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की भी विभागवार विस्तार से समीक्षा की।

संस्कारों की पाठशाला - किंडर बड्स स्कूल में कैलीग्राफी - रंग अक्षर कार्यशाला में सीखे गुर

कैलीग्राफी पुस्तक का विमोचन हुआ

सुबह सवेरे संवाददाता। संस्कारों की पाठशाला - किंडर बड्स स्कूल इंदौर में कैलीग्राफी - रंग अक्षर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया गया । नाम मात्र के रजिस्ट्रेशन शुल्क में विशेषज्ञ प्रतिष्ठा हासीजा ने प्रति दिन 3 घंटे गहन प्रशिक्षण अपनी स्वलिखित वर्कबुक के माध्यम से 10 से 50 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों , गृहिणियों , शिक्षिकाओं एवं अन्य प्रोफेसनल्स को निदेशक डॉ धीरज हासीज़ा , प्राचार्य डॉ दीपिका हासीजा की उपस्थिति में दिया। प्रथम दिवस सभी शिक्षिकाओं एवं स्टाफ के समक्ष गहन अनुभव से लिखी कैलीग्राफी पुस्तक का विमोचन हुआ। उक्त पुस्तिका के माध्यम से इस कार्यशाला में प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं कोर्स अंत पर सभी प्रतिभागियों को पुस्तक एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। समापन पर सभी ने अपने अनुभव खुशी खुशी साझा किए । प्रतिभागियों ने बताया कि इस से उन की लिखावट एवं व्यक्तित्व प्रभावशाली होंगा साथ ही स्कूल कालेज के असाइनमेंट प्रोजेक्ट लेखन में सुविधा होगी।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में संचालित की जा रही अनेक गतिविधियां

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार सीहोर जिले मे 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले भर में जल संरक्षण से संबंधित अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अभियान के तहत आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए दीवार लेखन, जागरूकता रैली, पोस्टर बैनर, रंगोली, ग्राम सभाएं, कलश यात्राएं, शपथ सहित अनेकों गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अभियान के तहत जिले के अनेक ग्रामों में कूप मरम्मत, तालाब जीर्णोद्धार, डैम की साफ-सफाई सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं तथा नागरिकों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई जा रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित खेत, तालाब, अमृत सरोवर, परकोलेशन टैंक, डगवेल, तालाब जीर्णोद्धार, जनभागीदारी के कार्य, कूप एवं बाउंड्री मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रमुख उद्देश्य जनभागीदारी से जल संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करना है।

मध्यप्रदेश जिला घरेलू उत्पाद रिपोर्ट देश में अभिनव

विजन 2047 की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार का है निर्णायक कदम

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर जिला विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को अब मूर्तरूप देते हुए जिला घरेलू उत्पाद रिपोर्ट तैयार की गई है। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उस सोच को साकार करने की दिशा में ठोस पहल है जिसके अनुसार

विकसित भारत का संकल्प देश के हर जिले में लिया जाएगा। यह पहल पूरे देश में अभिनव है। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा आज भोपाल में अटल बिहारी वाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में जिला घरेलू उत्पाद रिपोर्ट 2022-23 का विमोचन किया गया। अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला ने कहा कि डाटा आधारित नीति निर्माण के लिए जिला स्तर पर आर्थिक आंकड़ों का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने इसे मध्यप्रदेश के विजन 2047 की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिलों को आर्थिक विकास की धुरी बनाते हुए बॉटम अप दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। यह रिपोर्ट राज्य के सभी जिलों की आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है जो न केवल नीति निर्माण को डाटा आधारित बनाएगा साथ ही राज्य के विजन 2047 को जमीन पर भी उतारेगा। रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन जैसे जिलों ने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया है। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में भी यही जिले शीर्ष पर रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि वानिकी, पशुपालन, मछली पालन में राज्य का जीव्हीए में 45% का योगदान है जबकि द्वितीय क्षेत्र निर्माण और विनिर्माण तथा तृतीय क्षेत्र सेवाएं, व्यापार वित्त में क्रमशः 19% और 36% का योगदान दर्ज किया गया है। छिंदवाड़ा, धार, बालाघाट इंदौर और भोपाल जैसे जिलों ने विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी प्रदर्शन किया है।

कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यूपीएससी प्रतिभागी सम्मानित

प्रदेश के 58 कैंडीडेट्स का हुआ चयन, सीएम ने किया ई-ज्ञान सेतु का शुभारंभ

भोपाल। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2024 में पास 58 प्रतिभागियों का कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। कुल 58 प्रतिभागियों में से 15 युवतियां हैं। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएम ने ई-ज्ञान सेतु का शुभारंभ किया। इसके जरिए यूट्यूब व अन्य प्लेटफार्म पर बच्चों को स्टडी मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ऑनलाइन कोर्स, वीडियो ट्यूटोरियल, और अन्य सामग्री शामिल है। ई-ज्ञान सेतु पर मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग व बिजनेस से जुड़े स्टडी मटेरियल उपलब्ध होंगे। इसके लिए भोपाल व इंदौर समेत प्रदेश के 10 जिलों में डिजिटल स्टूडियो तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यूपीएससी में आज तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। मुझे बताया गया कि इस बार बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मंच छोटा पड़ गया। मेरी तो कामना है कि प्रदेश से इतने प्रतिभागी हो कि मंच के आगे की जगह भी कम पड़ जाए। अधिकांश सरकारी स्कूलों से निकलने वाले बच्चे हैं। यह हमारी गर्व की बात है। सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज, अभावों की उस पराकाष्ठा के बीच से निकले हैं। हमारे यहां तो लक्ष्मी का महत्व यदि किसी वनस्पती में है तो कमल में है और कमल तो कीचड़ में ही खिलते हैं। सीएम ने कहा कि अंग्रेजों के भारत में जब पाकिस्तान, बंगलादेश, भूटान समेत अन्य देश एक होते थे, उस समय आईसीएस होती थी। उस एग्जाम में अंग्रेजों को घमंड था कि हम बहुत महान हैं। हमारे खून में विशेष गुण हैं। वो भूल गए थे कि यह सत्ता सुख, राज्य और अधिकार, इससे आगे भी और कुछ है। उस दौर में आईसीएस की वो एग्जाम नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने 23 साल में पास की थी। उन्होंने एग्जाम के रिजल्ट में टॉप सूची में आने के बाद उस नौकरी को लात मार दी थी। यह देश महान हैं। यही कारण है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और गाय वाला आपके सामने बोल रहा है। बता दें कि ग्वालियर की आयुषी बंसल को 7वीं रैंक मिली है। इससे पहले आयुषी ने UPSC-2023 में 97वीं और 2022 में 188वीं रैंक हासिल की थी। आयुषी का जन्म ग्वालियर में हुआ है। माता-पिता दोनों LIC में काम करते थे। जब वे 5वीं क्लास में थीं, उनके पिता का निधन हो गया था। स्कूली पढ़ाई के बाद IIT की तैयारी के लिए वो दिल्ली आ गईं। यहां मैकेंजी एंड कंपनी में काम किया। 2022 में जॉब क्विट करके UPSC, CSE प्रिपरेशन शुरू की। ग्वालियर के ही माधव अग्रवाल ने 16वीं रैंक हासिल की है। साल 2019 में उन्होंने CA में टॉप रैंक हासिल की थी। उनके पिता राकेश अग्रवाल चाय व्यवसायी हैं। वहीं, रीवा के रोमिल द्विवेदी को 27वीं रैंक मिली है। रोमिल सहकारिता विभाग के जॉइंट कमिश्नर केके द्विवेदी के बेटे हैं। पिछले साल इनका सिलेक्शन ऑल इंडिया रेलवे सर्विस में हुआ था। इसी तरह मंदसौर जिले के गरोठ के रहने वाले ऋषभ चौधरी ने 28वीं रैंक हासिल की है। खास बात ये कि ऋषभ ने बिना कोचिंग के ही ये मुकाम पाया है। यूपीएससी क्लियर करने वाले 31 प्रतिभागी ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन सरकारी संस्थान से हुई है। इनमें यतीश अग्रवाल ने संस्कृत विषय से पढ़ाई की है। वहीं चंदेरी के विवेक भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं।

आईपीएस अफसरों से माफी मांगें जीतू पटवारी : डॉ. हितेष वाजपेयी

भोपाल। मध्यप्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉ. हितेष वाजपेयी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डॉ. वाजपेयी ने अपने बयान में कहा है कि जिस प्रकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रदेश के

तीन वरिष्ठ आईपीएस ऑफीसरों पर उनके प्रशासनिक आचरण पर नकारात्मक टिप्पणी करी है, संदिग्धता जाहिर करी है, यह बताता है कि कांग्रेस की सोच सभी देशभक्त वर्दी-धारियों के लिए न,केवल सेना के लिए अपितु पुलिस के लिए भी कितनी गिरी हुई है।

यह तीनों ऑफिसर्स हमारे डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं और उनके आचरण पर इस प्रकार के गलत लांछन लगाना कि इनका आचरण संदिग्ध है या ऐसी मंशा जाहिर करना, न केवल इनका अपमान है बल्कि सभी वर्दी धारी सेवाओं का अपमान है । मैं आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश की आईपीएस एसोसिएशन से की वे कांग्रेस के इन नेताओं को करारा जवाब दें और बताएं कि मध्य प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर अपनी दक्ष और कुशल कार्यशैली से पूरे देश में जाने जाते हैं। वे कांग्रेस के नेताओं से सर्टिफिकेट लेकर काम नहीं करते। हम कांग्रेस के इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि वह अपने इस बयान पर सभी आईपीएस अफसर से माफी मांगे।

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर भजनों के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि

भोपाल। आज भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नवाचार अपनाते हुए परंपरागत भाषणों के स्थान पर भक्ति संगीत और भजनों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। यह आयोजन मप्र कांग्रेस कार्यालय, शिवाजी नगर स्थित राजीव गांधी सभागार में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के तत्वावधान में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में मप्र कांग्रेस कमेटी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकारों ने भावपूर्ण भजनों एवं भक्ति संगीत की प्रस्तुति देकर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की स्मृतियों को सजीव किया और उनके योगदानों को स्मरण किया। आयोजन का उद्देश्य था- आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से प्रेरणादायक वातावरण के

माध्यम से श्रद्धांजलि देना।

इस अवसर पर मप्र कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिंह, प्रकोष्ठ एवं विभाग प्रभारी श्री महेंद्र चौहान, संगठन महामंत्री डॉ. संजय कामले, वरिष्ठ नेता श्री जे.पी. धनोपिया, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल, किसान कांग्रेस अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र चौहान, वरिष्ठ नेता श्री अरुण श्रीवास्तव, भोपाल शहर जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण सक्सेना, ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रीमती अनोखी पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। नेताओं ने स्व. राजीव गांधी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, आधुनिक भारत की नींव और युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों का स्मरण किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने यह कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां मनाई जाएंगी, जिससे विचार और भावना दोनों का समुचित समागम हो सके।

भोपाल-इंदौर मेट्रो में तुर्किए का ठेका, कांग्रेस का विरोध

मेट्रो ऑफिस का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी, बोले-कंपनी से अनुबंध खत्म किया जाए

भोपाल। भोपाल-इंदौर मेट्रो में तुर्किए की कंपनी 'असिस गार्ड' का ठेका है। वह स्टेशनों पर ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगा रही है। इसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भोपाल सांसद आलोक शर्मा का बयान सामने आ चुका है। वहीं, अब कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। बुधवार को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मेट्रो ऑफिस

का घेराव किया। यहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। शर्मा ने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है। ऐसे में देश खतरे में है। सॉफ्टवेयर के जरिए तुर्की देश को संकट में डाल सकता है। सात दिन के अंदर टेंडर निरस्त होना चाहिए। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि 7 दिन का वक्त दिया है। इस अवधि में मेट्रो कॉर्पोरेशन तुर्की का सामान निकाल लें, वरना मेट्रो ऑफिस के सामने ही बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट जीएम अजय गुप्ता को कांग्रेस ने ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान, प्रवीण सक्सेना, राहुल सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। एमपी मेट्रो कॉर्पोरेशन ने मेट्रो स्टेशनों पर ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन के लिए साल 2024 में इंटरनेशनल टेंडर कॉल किए थे। कुल 3 कंपनियों ने टेंडर भरे थे। इनमें से एक तुर्किए की असिस इलेक्ट्रॉनिक ब्लिसिम सिस्टमेलेरी भी शामिल है, जबकि दो अन्य कंपनी- एनईसी कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और शेलिंग फॉस्क ग्लोबल डिजिटल टेक्नोलॉजी थीं। 230 करोड़ रुपए के टेंडर कॉल के मुकाबले तुर्किए की कंपनी ने 186 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि टेंडर में दी थी। दूसरे स्थान पर एनईसी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने 204.57 करोड़ का प्रस्ताव सौंपा था। इस हिसाब से तुर्किए की कंपनी को टेंडर हासिल हो गया। टेंडर मिलने के बाद कंपनी ने स्टेशनों पर सिस्टम लगाने भी शुरू कर दिए। भोपाल में सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर और रानी कमलापति स्टेशन पर गेट्स लगाए जा चुके हैं जबकि डीआरएम तिराहा, अलकापुरी और एम्स में काम चल रहा है। इंदौर में भी 5 स्टेशन- गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर-3 तक सिस्टम इंस्टॉल किया जा चुका है। भोपाल और इंदौर के पहले फेस के कुल 53 स्टेशनों पर कंपनी काम करेगी। कंपनी के जिम्मे सबसे महत्वपूर्ण ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन यानी किराया लेने की पूरी प्रक्रिया का सिस्टम तैयार करने का काम है। जिसमें कार्ड के जरिए किराया लेने के बाद ही गेट खुलना भी शामिल है। यह कंपनी सिस्टम का पूरा मेंटेनेंस भी करेगी।

ड्रोन और कई सुरक्षा उपकरण बनाती है असिस गार्ड कंपनी- तुर्की की कंपनी असिस गार्ड ड्रोन सहित कई तरह के उपकरण बनाती है। ये बॉर्डर पर सुरक्षा के काम भी आते हैं। ASIS-GUARD रक्षा उद्योग के क्षेत्र में तकनीकी आवश्यकताओं के समाधान विकसित करने के लिए रोटरी विंग सशस्त्र/निरस्त्र ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल विजन और सीमा सुरक्षा प्रणाली और सैन्य वाहन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विकसित करती है। यह कंपनी अनुकूलित और संशोधित डिजाइन आवश्यकताओं के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशन देती है। पाकिस्तानी सेना ने 9 और 10 मई को भारत पर तुर्की निर्मित 'सोंगर' सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किया था। केंद्र सरकार ने भी कहा था कि यह अंकारा स्थित रक्षा कंपनी असीसगार्ड द्वारा विकसित सोंगर ड्रोन है। यह तुर्की सेना का पहला सशस्त्र ड्रोन है। पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सीमा के बहुत नज़दीकी इलाकों से लॉन्च किए गए थे। एसिसगार्ड की वेबसाइट पर उत्पाद पोर्टफोलियो पृष्ठ पर दी गई जानकारी के अनुसार, सोंगर पांच प्रकारों में उपलब्ध है, जिसमें एक गैर-घातक भूमिका वाला भी शामिल है। पांचों वैरिएंट में उनके हथियारों के आधार पर अंतर किया गया है। 5.56 × 45 मिमी असॉल्ट राइफल, 2 × 40 मिमी ग्रेनेड लांचर, 6 × 40 ड्रम-प्रकार ग्रेनेड लांचर, और 3 × 81 मिमी मोर्टार ग्रिपर। गैर-घातक संस्करण में आठ आंसू गैस या धुंआ गैस के कनस्तर तक ले जाया जा सकता है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा से बुधवार को प्रदेश कार्यालय में वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप-2025 में स्वर्ण पदक विजेता रोहित सिंह ने सौजन्य भेंट की। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने रोहित सिंह को स्वर्णिम उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की।

नर्मदापुरम एवं शाजापुर अमृत भारत स्टेशन एक नई पहचान की ओर

भोपाल। मंडल के अंतर्गत आने वाले नर्मदापुरम एवं शाजापुर रेलवे स्टेशनों को 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत नए स्वरूप में विकसित किया गया है। यह दोनों स्टेशन अब आधुनिक यात्री सुविधाओं, स्थानीय सांस्कृतिक पहचान और भव्य संरचनाओं के साथ अपनी नई पहचान के लिए तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मई 2025 को इन स्टेशनों का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा माना जाता है, और रेलवे स्टेशन किसी भी शहर की पहचान का केंद्र होते हैं। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने 1300 से अधिक स्टेशनों के पुनर्विकास का महत्वाकांक्षी कार्य प्रारंभ किया है। यह विकास केवल संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहल है जो स्टेशन को यात्रियों के लिए सुगम, सुसज्जित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। 26 करोड़ से अधिक की लागत से पुनर्विकसित नर्मदापुरम स्टेशन को स्थानीय संस्कृति और 'नर्मदा थीम' पर आधारित डिज़ाइन में ढाला गया है। स्टेशन पर भव्य प्रवेश द्वार, नवनिर्मित प्रतीक्षालय, मॉर्डन टिकट काउंटर, दिव्यांगजन अनुकूल रैंप व शौचालय, 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज तथा दोनों ओर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म पर विस्तृत शेड्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही, यात्रियों के लिए 3100 वर्गमीटर क्षेत्र में सौंदर्यीकृत सर्कुलेटिंग एरिया तथा 1000 वर्गमीटर में आधुनिक LED लाइटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह स्टेशन अब न केवल यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक केंद्र बनेगा, बल्कि माँ नर्मदा की पुण्यभूमि पर आधुनिकता और आस्था का संगम भी प्रस्तुत करेगा।

मध्यप्रदेश में भी नक्सलवाद को सफाए के लिए चल रहा अभियान : विष्णुदत्त शर्मा

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा सरकारें नक्सलियों को समाप्त करने के लिए संकल्पित

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सुरक्षा बल देशभर में नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कह चुके हैं कि देश के सिर्फ छह जिलों में ही नक्सली वर्तमान में सक्रिय हैं। उन्होंने मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकारें नक्सलियों को समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित हैं।

मध्यप्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मध्यप्रदेश के एक जिले बालाघाट में कुछ नक्सलियों की सक्रियता का पता चलता है। हाल ही में हमारे जाबांज सुरक्षा बलों ने बालाघाट के बिलालकसा गांव के पास नक्सलियों के मूवमेंट पर घेराबंदी की है। सुरक्षाबल नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को देश से समाप्त करने की जो समय-सीमा निर्धारित की है, उसके पहले ही मध्यप्रदेश से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जएगा।

छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही कार्रवाई सराहनीय

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बुधवार को ही छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों द्वारा अबूझमाड़ के जंगलों में दो दर्जन से अधिक नक्सलियों को मारे जाने की सूचना मिल रही है। मुठभेड़ में एक करोड़ से अधिक के इनामी नक्सली के भी मारे जाने की पुष्टि हुई है। यह कार्रवाई बताती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जो कहती है उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जो देश के लिए खतरा हां या देश की एकता या अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसे अवांछित गतिविधियों में संलिप्त किसी भी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।